आज का विचार
कुछ रिश्तों में लोग अच्छे लगते हैं... और कुछ लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं।

दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | बुधवार, 1 अप्रैल, 2026 | वर्ष 24, अंक 78, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

कांग्रेस की घोषणाएं डस्टबिन में जाती थीं, बीजेपी निभा रही हर वादा: नायब सिंह सैनी

तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, बोलेः हरियाणा को एक सप्ताह में मिल जायेंगे 2500 नये पटवारी

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में की गई घोषणाएं डस्टबिन में चली जाती थी। लेकिन इसके विपरीत, वर्ष 2014 से अब तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर संकल्प को पूरा करने की दिशा में ठोस कार्य किए है। वर्तमान सरकार घोषणाओं तक सीमित नहीं,बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रिप इरिगेशन पर सिंचाई विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम को सांसद चौधरी श्री धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांव सांगवान निवासी पर्वतारोही श्री प्रवीण को सम्मानित भी किया

मुख्यमंत्री ने रैली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम की यह धरती परिश्रम, त्याग और खेती-किसानी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल और स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए हरियाणा के लिए किये गये कार्यो का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के बनने के समय ही विकास की नई इबारत लिखी थी। वे तोशाम-लोहारू के बालू रेत के टीलों पर लहलहाती फसल देखना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पांच दशक पहले, उस समय विश्व स्तर का लिफ्ट इरिगेशन कैनाल सिस्टम तैयार किया था। इसके परिणामस्वरूप, इस रेतीले क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पहली बार नहरी पानी पहुंचा और लोगों की किस्मत बदली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने जो हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, वह हमारे लिए गर्व का विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक समर्पण के साथ काम करना है और हर उस वादे को पूरा करना है, जो हमने आपसे किया है। हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 60 वायदों को डेढ साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 157 वायदों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नॉनस्टॉप डबल इंजन सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को जमीन पर उतारकर दिखाया है।

पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्षी गलत बयानबाजी करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के 4,032 पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले बैठक ली है। उन्होंने जनता को आश्वासत करते हुए कहा कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्यों को सहयोग देना चाहिए, कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऋक्रभी दर्ज की हैं। गैस पाइपलाइन विस्तार के लिए सरकार ने लीज रेंट को 3 लाख से घटाकर मात्र 1 हजार रुपये कर दिया है, जिससे 13 लाख से अधिक घरों को ढठ्ऋकनेक्शन देने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा। सरकार आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि तोशाम में सरकार ने आईएमटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने किसानों से आान करते हुए कहा कि ई-भूमि पोर्टल को अगले एक सप्ताह में खोल दिया जाएगा। किसान इस पोर्टल पर जमीन पंजीकृत करवाये। किसी किसान पर दबाव नहीं होगा, लेकिन सरकार किसानों को उचित मूल्य देगी।

मेक इन इंडिया को मिली नई ताकत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद में केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के साणंद जीआईडीसी में केयन्स सेमीकॉन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक क्षण है और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही यहां कमर्शियल प्रोडक्शन भी आरंभ हो गया है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केयन्स सेमीकॉन सुविधा का उद्घाटन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत प्रयासों को और गति देता है तथा एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लायर के रूप में उभर रहा है। उन्होंने वर्ष 2021 में शुरू किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। इस मिशन के तहत छह राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये की लागत से 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 फरवरी को माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्लांट में उत्पादन शुरू हुआ था और अब 31 मार्च को केयन्स सेमीकॉन प्लांट भी उत्पादन के चरण में प्रवेश कर गया है। उन्होंने इसे संयोग नहीं, बल्कि भारत के तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रमाण बताया।

उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत की अपनी कंपनी केयन्स अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई है। आने वाले समय में और भी भारतीय कंपनियां वैश्विक सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगी। इस प्लांट में एडवांस्ड इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स (आईपीएमएस) का निर्माण किया जाएगा, जो ऑटोमोबाइल और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। ये मॉड्यूल्स उच्च दक्षता और विश्वसनीय पावर स्विचिंग सिस्टम के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स होती हैं और इनका निर्यात कैलिफोर्निया स्थित अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर को किया जाएगा। प्लांट के पूर्ण रूप से संचालित होने पर इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का प्रभाव अब वैश्विक स्तर पर दिखाई देगा और भारत में निर्मित उत्पाद दुनिया भर के उद्योगों को शक्ति प्रदान करेंगे। भारत का लक्ष्य घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर बाजार का वर्तमान आकार लगभग 50 अरब डॉलर है, जो इस दशक के अंत तक बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह वृद्धि भारत में इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को दशार्ती है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किए गए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत खनन और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा हालिया बजट में ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे तटीय राज्यों को जोड़ते हुए रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है, जो खनन, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एकीकृत श्रृंखला विकसित करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ही भारत ने यह संकल्प लिया था कि देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और वैश्विक हब के रूप में उभरेगा। आज उस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत अब देश में सेमीकंडक्टर उपकरणों और मटेरियल्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एक पूर्ण फुल-स्टैक इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

इस परियोजना के साथ भारत की दूसरी ओएसएटी/एटीएमपी यूनिट भी उत्पादन चरण में पहुंच गई है। यह देश की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनियों के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नालंदा के शीतला अष्टमी मेले में भगदड़ कम से कम आठ श्रद्धालुओं की मौत

एजेंसी (हि.स.)
पटना

बिहार के नालंदा जिले में मघड़ा गांव स्थित माता शीतलाष्टमी मंदिर में मंगलवार को भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद मंदिर परिसर और अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। अब तक दो मृतकों की पहचान सकुन्त बिहार निवासी दिनेश रजक की 50 वर्षीय पत्नी रीता देवी और मथुरापुर (नूरसराय) निवासी कमलेश प्रसाद की 45 वर्षीय पत्नी रेखा देवी के रूप में हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला देवी मंदिर में हुए भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 6 - 6 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ के अचानक बढ़ने और अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई, जिससे लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज चैत्र महीने का आखिरी दिन होने की वजह से मेला लगा था और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। जल्दी-जल्दी दर्शन कर लिया जाए, इसके लिए लोग एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। मंदिर का गर्भ गृह भी काफी छोटा है और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा जुटने की वजह से एकाएक भगदड़ मच गई और यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

ग्रामीण बोले-पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती नहीं

ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया है कि शीतला अष्टमी जैसे बड़े पर्व पर अपेक्षित संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। साथ ही, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना पर दुख जताते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था का आश्वासन देते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बताया जाता है कि इस मंदिर की देश के साथ-साथ विदेशों में भी मान्यता है। यहां चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मुख्य रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही 10 मार्च से ही शीतला माता का मेला शुरू हुआ था और आज आखिरी दिन था। इस वजह से काफी संख्या में यहां श्रद्धालु पूजा-पाठ करने पहुंचे थे। दरअसल, मघड़ा गांव बिहारशरीफ से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां शीतला अष्टमी के दिन विशेष परंपरा के तहत घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है।

राहुल गांधी ने पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में सोमवार सुबह टहलने निकले सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि दिनदहाड़े हुई यह हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक और कई समुदाय डर के साये में जीने को मजबूर हैं। भाजपा शासन में अपराधी बेखौफ और सुरक्षित हैं। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा उत्तराखंड आज हिंसा, हत्या और भय से घिरा हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजपुर थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में सोमवार सुबह करीब 6:50 बजे यह घटना हुई। मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के बीच गाड़ी को पास न देने पर विवाद हुआ। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा कर टायरों पर फायरिंग की। उसी दौरान एक गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे पूर्व ब्रिगेडियर को जा लगी। घायल ब्रिगेडियर वीके जोशी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

नालंदा विश्वविद्यालय का पतन केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी : राष्ट्रपति

एजेंसी (हि.स.)
राजगीर

बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने लगभग आठ शताब्दियों तक ज्ञान के एक महान केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, और इसका पतन न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, इसका पुनरुद्धार, आधुनिक परिवेश में विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत को फिर से स्थापित करने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्नातकों को डिग्रियां प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान के छात्रों को मानवता की एक साझी विरासत प्राप्त होती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यहां से स्नातक होने वाले छात्रों को दो चीजें मिलती हैं – एक डिग्री और एक विरासत। जहां डिग्री उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, वहीं मानवता की जो विरासत वे यहां से पाते हैं, वह एक साझी विरासत है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष स्नातक होने वाले छात्रों में से आधे से अधिक छात्र 30 से अधिक देशों के थे।

राष्ट्रपति ने कहा, भगवान महावीर और बुद्ध ने बिहार के इसी क्षेत्र से पूरी मानवता को अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया था। दीक्षांत समारोह से पहले उन्होंने पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, और 'नेट-जीरो उत्सर्जन' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह परिसर एक 'नेट-जीरो परिसर' बनने की अपनी यात्रा में, स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। उच्च शिक्षा संस्थानों को निश्चित रूप से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करना चाहिए।

डबल इंजन की सरकार असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ा रही : राजनाथ सिंह

एजेंसी (हि.स.)
शोणितपुर

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि डबल इंजन की सरकार आज असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ा रही है। असम विधान सभा चुनाव के मद्देनजर शोणितपुर जिला के तेजपुर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने भाजपानीत सरकार की उपलब्धियों की जहां चर्चा की, वहीं विपक्ष की कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान की रक्षा हो। असम के लोगों का सम्मान हो। यहां का विकास हो। इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार असम को विकास और समृद्धि के नए युग की ओर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा असम के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमेशा यहां की उपेक्षा की है। यहां के लोगों को कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से और दिमाग से भी दूर रखा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के कारण एक ऐसा समय था, जब असम के बारे में बात होती थी तो उग्रवाद की बात होती थी। अशांति की बात होती थी। अस्थिरता की बात होती थी। असम और नॉर्थ-ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्पित मंत्रालय बनाया था। ताकि असम और पूरे पूर्वोत्तर के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज जब पूर्वोत्तर की बात होती है तो विकास की बात होती है। कनेक्टिविटी की बात होती है। अष्टलक्ष्मी की बात होती है। यहाँ के संभावना की बात होती है। प्रगति की बात होती है। समृद्धि की बात होती है। आज, असम नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विकास का केंद्र बन रहा है। असम पूरे पूर्वोत्तर के विकास का इंजन बनकर उभर रहा है। जब असम आगे बढ़ेगा, तो पूरे भारत के विकास को रफ्तार मिलेगी। जब असम विकसित होगा तब ही भारत विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में भाजपा के शासन में असम की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के कार्यकाल में असम देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर सामने उभरा है। आज जब सरकार की सही नीति और नियति के साथ असम के लोगों की मेहनत और ऊर्जा मिली है तो असम ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। यहां उद्योग बढ़ा है। निवेश बढ़ा है। और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि असम ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग डेढ़ सौ बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। चिकित्सा हो या शिक्षा, आधारभूत संरचना हो या उद्योग, आज असम हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। यहां नए एम्स और आईआईएम जैसे संस्थान बन रहे हैं। हमारी सरकार ने 2035 तक असम के कई हजार स्कूलों को आधुनिक ड्रीम हब में विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे यहां के बच्चों को और भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यहां पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब 14 बन चुके हैं और 10 और बनने हैं। आज असम का स्वास्थ्य बजट 4000 करोड़ रुपये से बढ़कर 9000 करोड़ रुपये हो गया है। हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार काम कर रही है। पिछले वर्ष असम के नामरूप में प्रधानमंत्री ने यूरिया प्लांट की भी नींव रख दी है। हमने असम की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। 2009 से 2014 के मुकाबले हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। आज असम का रेलवे बजट 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पूर्वोत्तर को शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर भी मिलने वाला है। यह पूर्वोत्तर का पहला प्रवेश नियंत्रित उच्च गति गलियारा होगा। असम में 2014 तक सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थीं। लेकिन अब करीब-करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट्स चलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 6झ7 दशकों में यहां केवल तीन बड़े पुल ही बन पाए थे। पिछले सिर्फ दस वर्षों के दौरान हमने चार नए मेगा ब्रिज बनाए हैं। आज बोगीबील और धोलाझसदिया जैसे विशाल पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को नई ताकत दी है। आज असम बदल रहा है। आज असम शांति, विकास और विश्वास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जो राज्य कभी उग्रवाद की खबरों से सुर्खियों में रहता था, आज निवेश सम्मिट के लिए जाना जा रहा है। सही नीतियां और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो डर और हिंसा के दौर को पीछे छोड़ा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमने असम में सेमीकंडक्टर की परियोजना को आगे बढ़ाया है। इससे यहां के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। असम औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूएगा। कांग्रेस के लोगों को असम की कभी भी कोई चिंता नहीं रही है। कांग्रेस के लोग असम में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे इनका वोट बैंक मजबूत होता है। जब किसी राज्य की जनसांख्यिकी ही बदल दी जाए, तो उसकी संस्कृति, उसकी जमीन और उसके भविष्य पर कितना बड़ा संकट आ सकता है।

हिमाचल विस: शीतकालीन खेलों के लिए 73 करोड़ का बजट, डेयरी विकास पर सरकार का रोडमैप

दूध भुगतान का संकट अप्रैल तक होगा दूर; आईजीएमसी में शुरू होगी आधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा

विपक्ष ने घेरा: सड़कों के हस्तांतरण और दत्तनगर चिलिंग प्लांट में नुकसान पर उठाए गंभीर सवाल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विकास योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर तीखी चर्चा हुई। सरकार ने जहाँ शीतकालीन खेलों और स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लाने के लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान किया है, वहीं विपक्ष ने दूध के भुगतान और कार्यालयों के स्थानांतरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा।

विधायक अनुराधा राणा के सवाल के जवाब में आयुष मंत्री यादवेन्द्र गोमा ने बताया कि प्रदेश में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 7377 लाख रुपये खर्च कर रही है। लाहौल-स्पीति के जिस्पा में 333 लाख रुपये की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना है ताकि प्रदेश के खिलाड़ी वैश्विक पटल पर और पदक जीत सकें। दूध के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाते हुए सदस्य सतपाल सत्ती और अनिल शर्मा ने कहा कि किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2026 तक का भुगतान हो चुका है और फरवरी-मार्च का पैसा अप्रैल तक डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि डगवार प्लांट की क्षमता 1.5 लाख लीटर की जाएगी, जहाँ दूध के साथ घी भी बनाया जाएगा। दत्तनगर प्लांट में कांटा न होने से हो रहे नुकसान पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा रही है। इसके लिए 20 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हिमकेयर कार्ड धारकों को इसमें शामिल करने पर विचार चल रहा है और आम आदमी के इलाज के लिए 70 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्टाफ की कमी और उच्च लागत को लेकर चिंता जताई। शून्यकाल के दौरान विधायक बिक्रम सिंह ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया, जिस पर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। विधायक दीप राज द्वारा सड़कों के नाम न होने (म्यूटेशन) से आ रही दिक्कतों पर अध्यक्ष ने बताया कि नया कानून बनाया गया है, जिसके तहत सड़क के साथ 6 फीट का क्षेत्र हमेशा लोक निर्माण विभाग (ढहऊ) के नाम रहेगा। यह फाइल फिलहाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजी गई है।

विधानसभा परिसर में भाजपा का एंट्री टैक्स और सेस वृद्धि के खिलाफ का जोरदार प्रदर्शन

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने मंगलवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा एंट्री टैक्स में भारी वृद्धि और पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने के निर्णय के विरोध में विधानसभा परिसर में जमकर धरना-प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में एकजुट हुए भाजपा विधायकों ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी' करार देते हुए 'जनविरोधी मुख्यमंत्री किसने देखा, हमने देखा सबने देखा' जैसे तीखे नारों के साथ विधानसभा के मुख्य गेट तक मार्च किया, जहाँ मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तल्ख तेवरों में कहा कि एक तरफ केंद्र जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात देख देश में नागरिकों को पेट्रोल और डीजल के दाम में वैट दस रुपए घटाकर राहत दे चुकी है तो दूसरी और हिमाचल में सुक्खू सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जो न केवल प्रदेश की जनता की कमर तोड़ रहे हैं, बल्कि अब इन फैसलों की गूंज पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा तक पहुंच गई है, जहां के लोग और ट्रांसपोर्टर इस वृद्धि के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि छोटी गाड़ियों पर लगने वाले एंट्री टैक्स को चालीस रुपये से बढ़ाकर सीधे 170 रुपये और बड़ी गाड़ियों के लिए इसे एक हजार रुपये तक कर दिया गया है, जो न केवल तर्कहीन है बल्कि पर्यटन पर आधारित हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। यही नहीं विधानसभा में एक्ट पास कर पेट्रोल और डीजल में पांच रुपए विधवा और अनाथ सेस लगाकर जनता पर भारी बोझ लादने की तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष ने चिंता जताई कि सीमावर्ती जिलों के निवासियों के लिए यह निर्णय दैनिक आर्थिक उगाही जैसा बोझ बन जाएगा, जिससे आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप होने की कगार पर हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस टैक्स वृद्धि के विरोध में पड़ोसी राज्यों के लोगों ने आज रात से प्रदेश में वाहनों का प्रवेश बंद कर 'चक्का जाम' करने की चेतावनी दी है, जो राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। भाजपा ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न तो बिगड़ते हालात से कोई सबक ले रही है और न ही जनता के हितों के प्रति गंभीर है, बल्कि ऐसे अनावश्यक आर्थिक बोझ लादकर प्रदेश को आर्थिक अराजकता की ओर धकेल रही है। विपक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी और ईंधन पर लगाए गए सेस को तत्काल वापस नहीं लिया, तो सदन से लेकर सड़क तक इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, क्योंकि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण जहाँ एक ओर पर्यटन उद्योग को अपूरणीय क्षति हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की छवि भी बाहरी राज्यों में धूमिल हो रही है।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम की चुप्पी रहस्यमयी बेबस नजर आ रहे हैं सुक्खू: जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव से जुड़े कथित 'बेनामी सौदे' और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर शोर है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी विवशता और चुप्पी से भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा, यह मुमकिन ही नहीं कि सूबे के मुखिया को अपने सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आए एसडीएम स्तर के अधिकारी के फैसले की जानकारी न हो। सोशल मीडिया से लेकर सदन तक इस बेनामी डील (धारा 118 के उल्लंघन) पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोलकर सच्चाई से मुँह मोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस मामले में इतने 'कंप्रोमाइज्ड' हैं कि वे अपने कार्यालय के अधिकारियों के कमरे तक नहीं बदल पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पिछली सरकारों में संदिग्ध थी, आज वही लोग प्राइम पोस्टिंग पर बैठकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जिस अधिकारी को भ्रष्ट बताकर हटाने की मांग की थी, सत्ता में आते ही उसे अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बना लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सरकार में अधिकारियों के बीच 'सिर-फुटौव्वल' की स्थिति है, जो मुख्यमंत्री की कमजोर पकड़ का प्रमाण है।

घर के अंदर फंदे से लटका मिला 19 वर्षीय युवक का शव

शिमला। शिमला जिले के उपमंडल नेरवा के आरोग गांव में 19 वर्षीय युवक का शव उसके घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम को आरोग गांव निवासी मनोहर शर्मा ने मोबाइल फोन के माध्यम से थाना नेरवा में सूचना दी कि उनके गांव के रहने वाले मुनीश उर्फ सोनू (19 वर्ष), पुत्र दुलवी राम ने अपने घर के अंदर फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि मौके पर मृतक के पिता दुलवी राम की उपस्थिति में कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान युवक का शव कमरे के अंदर छत पर पंखे के लिए लगी लोहे की कुंडी से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेरवा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शव का पोस्टमार्टम किया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

लेह-मनाली हाईवे: तंगलंग ला पर जमी 15 फीट बर्फ हटाने की जंग अंतिम चरण में, अप्रैल अंत तक बहाली की उम्मीद

17,482 फीट की ऊंचाई और -8 डिग्री तापमान के बीच बीआरओ का अभियान; लेह से पांग तक साफ हुआ रास्ता

एजेंसी (हि.स.)
लेह/श्रीनगर

लेह/श्रीनगर, 31 मार्च, 2026: लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 'लेह-मनाली जीवनरेखा' को बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन (इफ्ढ) के जांबाज शून्य से नीचे के तापमान में दिन-रात जुटे हुए हैं।

17,482 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक 'तंगलंग ला' पर बर्फ हटाने का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बीआरओ की 111 आरसीसी टीम ने लेह की ओर से इस चुनौतीपूर्ण हिमालयी दर्रे तक सड़क को सफलतापूर्वक साफ कर दिया है, जिससे अब अप्रैल के अंत तक यातायात पूरी तरह बहाल होने की प्रबल संभावना बन गई है। बीआरओ अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले साल की तुलना में 10 से 15 फीट अधिक बर्फ जमा हुई है, जिससे ऑपरेशन को और अधिक जटिल बना दिया है। भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के बीच बीआरओ की टीमें अब पांग तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि, अभी भी लगभग 140 किलोमीटर का हिस्सा साफ किया जाना बाकी है, जिस पर काम युद्धस्तर पर जारी है। तंगलंग ला टॉप पर काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां का तापमान वर्तमान में -8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे मशीनों और इंसानों दोनों की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। लगातार खराब मौसम के कारण मार्च के शुरूआती हफ्तों में कार्य बाधित हुआ था, लेकिन 16 मार्च से शुरू हुए इस महा-अभियान में अब तेजी आई है।

बीआरओ ने इस मिशन के लिए अत्याधुनिक स्नो कटर, भारी एक्सकेवेटर, डोजर और स्नो ब्लोअर जैसी मशीनरी तैनात की है। 'प्रोजेक्ट हिमांक' के इंजीनियरों और ऑपरेटरों के साथ-साथ स्थानीय मजदूर भी इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस मार्ग का खुलना न केवल सेना की रसद आपूर्ति के लिए जरूरी है, बल्कि यह लद्दाख में पर्यटन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए भी अनिवार्य है।

संक्षिप्त-समाचार

पीर गली में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मुगल रोड अस्थायी रूप से बंद

पुंछ। पीर गली में रात भर हुई भारी बारिश और बर्फबारी के कारण मुगल रोड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक रूरल फारूक कासियर ने बताया कि सड़क तब तक बंद रहेगी जब तक यात्रा के लिए स्थिति सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती। मार्ग के सुरक्षित होने और उसकी पुष्टि होने के बाद ही उसे दोबारा खोलने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मुगल रोड पर गैर-जरूरी यात्रा से बचें और प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतें।

रामबन में भूस्खलन से यातायात बाधित जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर आवागमन रुका

जम्मू। रामबन जिले के मेहर के पास भूस्खलन के कारण अप और डाउन दोनों ट्यूब अवरुद्ध हो जाने के बाद सोमवार रात जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि यह भूस्खलन ट्रेलर पार्किंग क्षेत्र के पास हुआ जिससे उस मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ से बचने के लिए चंदरकोट, जाखियानी खरपुरा और किस्तवाडी पथेर पर यातायात रोक दिया है। अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू किए है।

शोपियां में आकस्मिक गोलीबारी की घटना में कांस्टेबल की मौत

शोपियां। मंगलवार को शोपियां जिले में आकस्मिक गोलीबारी की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। शोपियां के नूरपोरा निवासी 36 वर्षीय कांस्टेबल रविवार को ड्यूटी के दौरान घायल हो गए, जब उनके एक साथी कांस्टेबल ने गलती से अपनी सर्विस गन चला दी। गोली उनके पेट के दाहिने हिस्से में लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए सेना बेस अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए एसकेआईएमएस सौरा रेफर कर दिया गया। एसकेआईएमएस में उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि निरंतर चिकित्सा देखभाल और हस्तक्षेप के बावजूद, कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया अधिकारियों ने पुष्टि की। अधिकारियों ने आकस्मिक गोलीबारी की घटना के सटीक घटनाक्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

जेकेएएस अधिकारी संदीप सिंह बाली निलंबित, सरकार ने दिए जांच के आदेश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अनंतनाग के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) संदीप सिंह बाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, निलंबन आदेश कुछ आरोपों की जांच लंबित रहने तक जारी किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से संबद्ध रहेंगे। सरकार ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच भी शुरू की है। निलंबन के कारणों के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कांगड़ा में खौफनाक वारदात: कुटाहण गांव में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की पत्नी की हत्या

कांगड़ा। लंबागांव क्षेत्र के कुटाहण गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान सन्नी कुमार निवासी लंबागांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को वह अपनी पत्नी काल्टी देवी को झाड़-फूंक के लिए कहीं लेकर गया था। देर रात करीब 12 बजे वह अपनी पत्नी को लेकर कुटाहण में अपने भाई के घर पहुंचा। सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे आरोपी ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय आरोपी का भाई दूसरे कमरे में सो रहा था। जैसे ही उसे वारदात का पता चला, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। मृतका के पीछे दो छोटे बेटे और एक बेटी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से बीड़ बैजनाथ का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार पिछले कई दशकों से लंबागांव में रह रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिमाचल विस में गूंजा सेब का मुद्दा: अमेरिकी आयात शुल्क शून्य हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे बागवान

शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले सेब उद्योग पर मंडराते संकट को लेकर मंगलवार को विधानसभा में गंभीर चर्चा हुई। ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा लाए गए संकल्प प्रस्ताव पर सदन ने एकमत होकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। राठौर ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका (वाशिंगटन) से आने वाले सेब पर आयात शुल्क शून्य किया गया, तो प्रदेश के 2 लाख बागवान परिवार बबार्दी की कगार पर पहुँच जाएंगे।कुलदीप राठौर ने आंकड़ों के जरिए हिमाचल और अमेरिका के सेब उत्पादन की तुलना की। उन्होंने बताया कि हिमाचल में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मात्र 6 से 7 टन है, जबकि अमेरिका में यह 50 से 80 टन है।

अब सड़क निर्माण में होगा श्रेडेड प्लास्टिक का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगी रोक

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

हिमाचल प्रदेश की सड़कों के निर्माण में अब श्रेडेड प्लास्टिक का उपयोग होगा। वहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से रोक लगेगी। प्रदेश के पर्यावरण से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। इस बारे में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एनजीटी से संबंधित विभिन्न मामलों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण, चालान, प्लास्टिक जब्ती तथा प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को प्राथमिकता देते हुए इसे सड़क निर्माण, सीमेंट संयंत्रों तथा अन्य स्वीकृत माध्यमों के माध्यम से उपयोग में लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि तरल एवं ठोस कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना नगर निकायों की जिम्मेदारी है तथा इस कार्य में संलग्न सभी डिस्लजर एवं ठेकेदारों का नगर निकायों तथा खंड (ब्लॉक) कार्यालयों में पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल को केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही डंप किया जाए तथा इसे खुले में, नालों अथवा खड्डों में बहाने की किसी भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपमंडल अधिकारियों एसडीएम एवं खंड विकास अधिकारियों बीडीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए मल का निस्तारण केवल अधिकृत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अथवा यांत्रिक डिस्लजर के माध्यम से ही किया जाए।

रोहडू में चार युवकों से पकड़ा चिट्टा, मामला दर्ज

शिमला। शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र में पुलिस ने चार युवकों के कब्जे से 3.66 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम थाना रोहडू में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए प्रिंस देशटा पुत्र रमेश देशटा निवासी सैंजी, अंकित चांजटा पुत्र भूपिंदर निवासी छाजपुर, रजनीश ठाकुर पुत्र सोहन ठाकुर निवासी अडाल और वीरेन्द्र देशटा पुत्र केहर सिंह निवासी समोली, रोहडू के कब्जे से 3.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही चिट्टे की मात्रा कम होने की वजह से आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और मादक पदार्थ की आपूर्ति से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

पेट्रोल-डीजल सेस और एंट्री टैक्स के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी भाजपा: डॉ. राजीव बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 5 रुपये अतिरिक्त सेस लगाने और एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी के फैसले ने राज्य में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की पटकथा लिख दी है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार के इन फैसलों को 'जनता की जेब पर डाका' करार देते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इन जनविरोधी फैसलों को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो पार्टी 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन करेगी। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं का बोझ आम जनता, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर डाल रही है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिसका सीधा असर खाद्य वस्तुओं और निर्माण सामग्री की कीमतों पर पड़ेगा। डॉ. बिंदल ने चेतावनी दी कि हिमाचल का हर वर्ग–चाहे वह टैक्सी ऑपरेटर हो, बस मालिक हो या आम उपभोक्ता–इस महंगाई से त्रस्त है और भाजपा इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी। हिमाचल सरकार द्वारा एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी का असर केवल प्रदेश के भीतर ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी दिखने लगा है। भाजपा का कहना है कि इस टैक्स के कारण हिमाचल के सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

रिंग रोड पर खूनी वारदात: भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

एजेंसी (हि.स.)
दोमाना (जम्मू)

जम्मू के रिंग रोड इलाके में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा (इख ट) के फ्लांय मंडल अध्यक्ष और सरदारे चक निवासी सचिन गुप्ता पर नकाबपोश हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना उस समय हुई जब सचिन अपने एक साथी के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। गंभीर रूप से घायल सचिन को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अमृतसर रेफर किया गया है।

पुलिस को दिए गए शुरूआती बयान में घायल सचिन ने गांव के ही दो व्यक्तियों पर हमले का संदेह जताया है। सूचना मिलते ही फ्लांय मंडाल चौकी प्रभारी नरेश कैथ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी (उउळश) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सचिन गुप्ता सोमवार सुबह अपने साथी बबलू के साथ रिंग रोड पर टहल रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवक उनके पास पहुंचे। हमलावरों ने पहले सचिन से उनकी पहचान पूछी। जैसे ही सचिन ने अपना नाम और पता बताया, बाइक के पीछे बैठे युवक ने अचानक धारदार हथियार निकाला और सचिन पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए।

सचिन को खून से लथपथ देख उनके साथी बबलू ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों पर पत्थर बरसाने शुरू किए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल सचिन को तुरंत सोहांजना अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया।

सदन | स्थानीय स्तर पर भर्ती की मांग वाले निजी विधेयक पर चर्चा

हर किसी को घर के पास नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी: सीएम

उमर अब्दुल्ला ने गिनाईं प्रशासनिक चुनौतियां

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय स्तर पर नियुक्तियों और तबादलों को लेकर एक महत्वपूर्ण नीतिगत स्पष्टीकरण दिया है। विधानसभा में विधायक निजामुद्दीन भट द्वारा पेश किए गए एक निजी विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि हर किसी को उसके घर के पास सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्तियों को केवल स्थानीय स्तर (ब्लॉक या जिला) तक सीमित रखने से न केवल प्रशासनिक जटिलताएं बढ़ेंगी, बल्कि इससे पदोन्नति में असमानता और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि भर्ती के बाद कर्मचारी, विशेषकर डॉक्टर, अपने गृह जनपद या घर के आसपास ही तैनाती के लिए सिफारिशें लगवाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गांदरबल का डॉक्टर बांदीपोरा जाने से भी कतराता है, जबकि यह महज एक घंटे का सफर है। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि यदि भर्ती को स्थानीय स्तर तक सीमित किया गया, तो आरक्षित कोटा पूरा करना मुश्किल होगा और योग्य उम्मीदवारों की कमी होने पर नियमों में छूट देनी पड़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार और मनमानी का रास्ता खुल सकता है। मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि क्यों स्थानीय स्तर पर कैडर बनाना व्यावहारिक नहीं है। उनके अनुसार, यदि ब्लॉक स्तर पर भर्तियां की जाती हैं, तो बड़े ब्लॉक के कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे, जबकि छोटे ब्लॉक में अवसर सीमित रह जाएंगे। इससे एक ही समय पर भर्ती हुए दो कर्मचारियों के करियर ग्राफ में बड़ा अंतर आ जाएगा, जो पूरी तरह से नाइंसाफी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को समझती है, लेकिन यह विधेयक उसका सही समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कि सरकार इस चिंता को दूर करने के लिए वैकल्पिक और बेहतर उपायों पर विचार करेगी, विधायक निजामुद्दीन भट ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। सदन में भाजपा विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने मंदिरों के संरक्षण और अवैध कब्जे वाली भूमि की वापसी के लिए एक प्रस्ताव रखा था। इसका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर–सभी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक मनकोटिया ने दावा किया कि 1987 के बाद प्रदेश में मंदिरों की स्थिति खराब हुई है और कई जगहों पर जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1842 ऐसे मंदिर चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने मांग की कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन मंदिरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

तोशाम उन्नत सिंचाई उत्सव-2026 में मुख्यमंत्री ने दी बड़ी सौगातें

मुख्यमंत्री ने 107 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को जिला भिवानी के तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव-2026 के दौरान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देते हुए 107 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 13 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से पूर्ण दो परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 93 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से चार नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करना, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया इनमें बिडोला में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण 712.54 लाख रुपये की लागत से तथा ढिघावा जाटान में स्कूल भवन का निर्माण 685.99 लाख रुपये की लागत से शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री द्वारा जिन चार नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया इनमें 33 केवी सब स्टेशन लोहारू का निर्माण 811.61 लाख रुपये की लागत से, 33 केवी सब स्टेशन लोहारू इशरवाल का निर्माण 319.49 लाख रुपये की लागत से, 33 केवी सब स्टेशन भाकड़ा का निर्माण 607.26 लाख रुपये की लागत से तथा गरवा गांव में एक्वा पार्क का निर्माण 7,623.90 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता के साथ लागू किया है। भिवानी क्षेत्र के विकास में भी किसी भी तरह की कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। तोशाम हलके में किए गए काम काज का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री ने इस बीच जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तोशाम हलके के विकास को गति देने के लिए वर्तमान सरकार के साढ़े 11 वर्षों के कार्यकाल में 283 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 258 का काम पूरा हो चुका है तथा शेष पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी मार्गदर्शन है।

'विकसित भारत 2047' का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों के सामने रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। यह ऐसा संकल्प है, जिसमें देश का हर नागरिक भागीदार है। हम सब मिलकर 'विकसित हरियाणा' के माध्यम से 'विकसित भारत' के सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ खड़ी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे बात कोराना काल की हो या फिर अफगानिगस्तान से भारतीयों को सकुशल वापिस लाने का कार्य जब भी वैश्विक संकट आया पीएम मोदी हमेशा जनता के साथ रहे। लेकिन मुझे दुःख होता है कि विपक्षी पार्टी के लोग वैश्विक संकट के समय में झूठी बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर विकास को नई गति प्राप्त होगी।

हरियाणा में 1 अप्रैल से 15 मई तक रबी खरीद के लिए मंडियों में व्यवस्था चाक चौबंद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और एजेंसी के जिला प्रबंधकों को विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया गया : राजेश नागर
- रबी खरीद 2026-27 को मंडियां और प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त

हरियाणा में रबी खरीद 2026 - 27 की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार 1 अप्रैल से हरियाणा में रबी की सरकारी खरीद का आगाज होना है। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि रबी खरीद 2026-27 के मद्देनजर प्रदेश की अनाज मंडियों को तैयार कर लिया गया है। मंडी परिसर में साफ सफाई और किसान भाइयों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बाबत जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और एजेंसी के जिला प्रबंधकों को विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया गया है।

श्री नागर ने बताया कि मंडियों में बायोमेट्रिक आधारित खरीद होगी, प्रक्रिया को सरल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वयं किसान या उनके द्वारा मनोनीत 3 नॉमिनियों में से केवल एक का ही बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के कारण उसे खुद खेत छोड़कर आना नहीं होगा। इसके अलावा सभी मंडी स्थानों की जिओ फेंसिंग की गई है। इस सुविधा के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी गेट पास, नीलामी, जे फंड बनाने और लिफ्टिंग से संबंधित गतिविधियां केवल मंडी परिसर के भीतर की जाएँ। इसके लिए मंडी के जिओ फेंस किये गए क्षेत्र के भीतर उपस्थिति को सत्यापित किया जाता है. जिससे राज्य के किसान की फसल को कोई अन्य व्यक्ति किसान के नाम पर फर्जी तरीके से बेच न सके।

किसानों को गेट पास जारी करते समय, वाहन के फोटो के साथ साथ वाहन नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसलिये मण्डी मे फसल लेकर आने वाले वाहनो पर नम्बर प्लेट ना होने पर किसान अपने वाहन पर पेंट या हाथ से एक कागज पर लिख कर भी चिपका कर आ सकता है, उसे भी मान्य किया गया है।

साथ ही, निकास गेट पास (ए७३ ऱ्ह्री ढं२२) केवल तभी जारी किया जा सकता है, जब संबंधित वाहन मंडी के जियो-फेंस किए गए क्षेत्र के भीतर मौजूद हो। उन्होंने बताया कि सभी भंडारण स्थलों की जियो फेंसिंग यह सुनिश्चित करती है कि खाद्यान्नों की गोदामों में प्राप्ति तभी हो सकेगी, जब वाहन भौतिक रूप से भंडारण स्थल के जियो-फेंस किए गए क्षेत्र के भीतर मौजूद हो।

राज्य के किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत है, से उनकी उपज की पूर्ण खरीद की जायेगी। कृषि विभाग ने किसानों द्वारा घोषित भूमि पर उगी फसल के सत्यापन के लिए उपग्रह-छवि (२३ी'ॅ३ी ॅ) आधारित प्रणाली शुरू की है। राजस्व और जिला कृषि अधिकारियों के सत्यापन के साथ-साथ, तीसरे स्तर के सत्यापन के रूप में ऌअफअउ के माध्यम से हीट मैप्स का उपयोग किया जाता है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान महावीर जयंती पर किया नमन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर भगवान महावीर को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया।

चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान महावीर के उपदेश अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आत्मसंयम आज भी प्रासंगिक हैं और मानव को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के संदेश समाज में शांति, भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक बेहतर और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान महावीर के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में प्रेम, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अहिंसा और सत्य के मार्ग का पालन करेंगे तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।

गेहूं खरीद, उठान, भंडारण और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की रहेगी नजर: विश्राम कुमार मीणा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- मंडियों और खरीद केन्द्रों पर आज से शुरू होगा खरीद कार्य
- मंडियों और खरीद केन्द्रों के अनुसार नियुक्त किए नोडल अधिकारी, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से रहेगी परिवहन व्यवस्था पर नजर

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद कार्य को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इस सीजन में गेहूं खरीद कार्य, उठान, भंडारण व अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नजर रहेगी। इन नोडल अधिकारियों के साथ-साथ मार्किट कमेटी के सचिव, निरीक्षक के साथ-साथ अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी रहेगी।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मंगलवार को अधिकारियों को खरीद कार्य को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं और गेहूं खरीद कार्य को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी, परिवहन प्रबंधक व कष्ट निवारण समिति नियुक्त की है। इसके लिए पिपली मंडी हेतु एडीसी विवेक आर्य, कुरुक्षेत्र, अमीन, किरमच, बारना व लुखी के लिए एसडीएम अमन कुमार, पिहोवा, एक्सटेंशन मंडी पिहोवा, गुमथला गढू व थाना के लिए एसडीएम पिहोवा अनिल कुमार दून, भौर सैयदा के लिए नायब तहसीलदार सागर मल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि बोधनी, कराह साहब, नीमवाला व ईशाक के लिए तहसीलदार पूनम सोलंकी, इस्माईलाबाद, मलिकपुर व ठोल के लिए नायब तहसीलदार बलविन्द्र, झांसा, अजराना कला व शाहबाद के लिए सीईओ जिला परिषद शम्भू राठी, नलवी, चढुनी जाटान के लिए तहसीलदार नवनीत, लाडवा व बाबैन मंडी के लिए एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता व नायब तहसीलदार गीता राम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इन सभी नोडल अधिकारियों के साथ 5 से 10 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि मंडियों में उठान व परिवहन व्यवस्था पर विशेष फोकस रखा जाएगा। ट्रकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जीपीएस ट्रैकर भी लगा होना चाहिए। इसके साथ ही समन्वय के लिए ठेकेदारों के साथ नियमित बैठक की जाए और दैनिक कार्य पर निगरानी रखी जाए। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एवं एंट्री व एग्जिट सिस्टम की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भंडारण की व्यवस्था, स्टाफ की उपलब्धता, फोटो व वाहन विवरण, बायोमीट्रिक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम सहित अन्य व्यवस्थाओं पर भी निगरानी रखी जाए।

उपायुक्त ने कहा कि मंडियों में किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें डीएमईओ राजीव चौधरी, एचएसएएमवी के कार्यकारी अभियंता सतीश कुमार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक, डीएम हैफेड शमशेर सिंह, डीएफएससी नरेश कुमार को शामिल किया गया है।

संक्षिप्त-समाचार

हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने सिसवान झील और वन अभ्यारण्य का दौरा किया

चंडीगढ़। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने, लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष के साथ, मंगलवार को सिसवान झील और उसके साथ लगते हुए वन अभ्यारण्य के शांत वातावरण का दौरा किया और वहां की मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक समृद्धि का अनुभव किया। इस दौरान, माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष और हरियाणा लोक भवन के सचिव श्री डी.के. बेहेरा ने मोटरबोट की सवारी की और शिवालिक पहाड़ियों के आसपास के नजारों का अवलोकन किया। उन्होंने वहां स्थित संग्रहालय का भी दौरा किया, जिसमें क्षेत्र की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है और जिसे विभाग द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है। वहां के स्वच्छ वातावरण, शांत जल और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे से अत्यंत प्रभावित होकर, हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रो. घोष ने इस प्राकृतिक और छिपे हुए स्थल को संरक्षित करने के लिए पंजाब के वन विभाग के प्रयासों की सराहना की। मंडल वन अधिकारी श्री अमनीत सिंह (आईएफएस) ने उन्हें झील के महत्व, वन अभ्यारण्य की जैव विविधता और पंजाब के वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर, पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त श्री हरप्रीत संधू ने सम्मान और स्मृति चिह्न के रूप में, माननीय राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और लेडी गवर्नर श्रीमती मित्रा घोष को सिसवान झील का एक चित्र, साथ ही उनके नाम की पट्टिकाएं और फूलों के गमले भेंट किए। इस अवसर पर राज्यपाल के एडीसी श्री नीतीश अग्रवाल, एसएमओ डॉ. राजेश तलवार, राज्यपाल के निजी सचिव श्री शंख चटर्जी और हरियाणा लोक भवन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग ने अंबाला में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय - स्तरीय शहीद स्मारक के चल रहे कार्यों की समीक्षा की

चंडीगढ़। हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग ने वर्तमान में पूर्ण हो चुके कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और लंबित कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने समग्र कार्य योजना की समीक्षा के लिए बैठक भी की और आवश्यक निर्देश जारी किए। बैठक के बाद, उन्होंने शहीद स्मारक पर चल रहे कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्मारक के मुख्य द्वार के बाहर साफ-सफाई बनाए रखने और अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए ठलअकविभाग के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। महानिदेशक श्री पांडुरंग ने कहा कि स्मारक से संबंधित सभी फिनिशिंग (अंतिम रूप देने वाले) कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि उचित 'लेवल चेकिंग' (स्तर की जांच) की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बरसात के मौसम में पानी जमा न हो, और स्थल पर लगाए गए सभी मैनहोल आवश्यक स्तरों के अनुसार स्थापित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिजली, सीवरेज और अन्य सेवाओं से संबंधित कार्यों की जांच एक समर्पित टीम बनाकर 'थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन' (किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जांच) के माध्यम से की जानी चाहिए।

एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर विनोद कुमार सिंगला 34 साल की सेवाएं देने के उपरांत हुए सेवानिवृत

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर विनोद कुमार सिंगला ने कुरुक्षेत्र के विकास और प्रचार प्रसार के लिए एक सराहनीय, उल्लेखनीय उत्कृष्ट सेवाएं दी है। इन सेवाओं की बदौलत देश विदेश के लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ जुड़े रहे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। इन सेवाओं को जिला प्रशासन कभी भूला नहीं पाएगा।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा लघु सचिवालय के सभागार में एनआईसी विभाग की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, नगराधीश आशीष कुमार, केडीबी सीईओ पंकज सेतिया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेन्द्र सिंघल, डीआईपीआरओ डा. नरेन्द्र सिंह, लेखा अधिकारी सत्य भूषण, एडआईओ भारती ने एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर विनोद कुमार सिंगला को सेवानिवृति पर बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ-साथ यादगारी के लिए एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

एडीआईओ भारती ने कहा कि एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर विनोद कुमार सिंगला ने 28 फरवरी 1992 को सरकारी सेवाएं ज्वाइन की और पहली पोस्टिंग महिला एवं बाल विकास जींद में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में रही। इसके बाद 1997 में एनआईसी हैड क्वाटर नई दिल्ली में साईटिस्ट पद पर अपनी सेवाएं दी और 1999 में कुरुक्षेत्र एनआईसी कार्यालय में तबादला हुआ। तब से लेकर अब तक सीनियर डायरेक्टर विनोद सिंगला ने कुरुक्षेत्र में ही सेवाएं दी। इन सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर विनोद कुमार सिंगला ने प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पग-पग पर सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका सहयोग किया। इसके साथ ही उनके परिवार का भी हमेशा साथ रहा है। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी आर्यदीप आर्य, बेटे आदिविक, नितिन सिंगला, चारू, आरवी, सुरेन्द्र सिंगला, ऊषा, सरोज, निर्मल, सुनीता, दिवाकर, मुकेश, विक्रम आदि उपस्थित रहे।

बाऊजी ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया: पवन गर्ग

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र लोकसभा के पूर्व सांसद एवं हरियाणा सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री ओम प्रकाश जिन्दल की पुण्यतिथि पर ओपी जिन्दल पार्क में श्रद्धापूर्वक उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकताओं एवं क्षेत्रवासियों ने उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बाऊजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाऊजी ओम प्रकाश जिन्दल जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर समाजसेवी पवन गर्ग ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंग साझा किए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जिन्दल केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जनमानस के सच्चे नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया।

उन्होंने विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, वंचितों और किसानों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, जिसके कारण वे आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके कार्यों और विचारों ने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

उन्होंने कहा कि बाऊजी ओम प्रकाश जिन्दल जी के आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य उनके सुपुत्र एवं वर्तमान सांसद नवीन जिन्दल निरंतर कर रहे हैं। वे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

इस अवसर पर पंडित कर्मचंद शर्मा, महिपाल अमीन, सतपाल सरपंच धुराला, सुखविंदर सरपंच, सोहन सैनी सरपंच जसविंदर सैनी सरपंच, नफे सिंह गुर्जर पूर्व सरपंच, रॉकी सैनी, सज्जू गुर्जर, गुरदीप प्रजापत, जगपाल सिंह, बलदेव कल्याण एडवोकेट, प्रतिमा रानी, मनदीप कौर, प्रवीण सैनी सरपंच, हरि ओम अग्रवाल, जगदीश नेहरा, श्रीराम शर्मा, परमजीत सरपंच, राजेन्द्र राजपूत, शाहबाद हल्का प्रभारी अजैब सिंह, पिहोवा हल्का प्रभारी जीत राम और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम, 134-ए के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान किया जारी: महीपाल ढांडा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 134-ए के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस एवं बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान राशि जारी कर अपने वादे को पूरा किया है।

विभाग द्वारा कुल 31.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिससे राज्य के सात जिलों—अंबाला, गुरुग्राम, फतेहाबाद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक—के निजी विद्यालयों को लाभ प्राप्त हुआ है।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की समावेशी शिक्षा नीति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना निरंतर प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस अनुदान से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों को भी समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।

श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 134-ए के तहत दी जा रही यह सहायता उसी दिशा में एक सार्थक पहल है।

उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी इसी प्रकार पारदर्शिता और तत्परता के साथ योजनाओं को लागू करता रहेगा, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि समाज में समानता और समावेशिता को भी बढ़ावा देगी।

हरियाणा में बढ़ता प्रदूषण और घटती हरियाली, जवाबदेही की जरूरत: कुमारी सैलजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- कई जिलों में हरियाली की स्थिति चिंताजनक है, जहां लगाए गए पौधों का बहुत कम प्रतिशत ही जीवित है
- योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं और निगरानी व्यवस्था भी कमजोर है

सिरसा से लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने हरियाणा में लगातार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और घटती हरियाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बड़े-बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में वन क्षेत्र में कमी आई है और करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद लगाए गए पौधों का बड़ा हिस्सा जीवित नहीं रह पाया। यह स्थिति दशार्ती है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं और निगरानी व्यवस्था भी कमजोर है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि कई जिलों में हरियाली की स्थिति चिंताजनक है, जहां लगाए गए पौधों का बहुत कम प्रतिशत ही जीवित है। इससे साफ है कि पर्यावरण संरक्षण केवल कागजों और बयानबाजी तक सीमित रह गया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी का परिणाम बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस विभाग पर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है, वहीं पर अनियमितताओं और घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं। वन विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, जिससे जंगलों की सुरक्षा और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अवैध कटाई की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। नदियों और नालों के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर लोगों को दूषित पानी मिल रहा है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

उन्होंने मांग की कि जल स्रोतों की नियमित जांच हो और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस की नीति का उल्लेख करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा संतुलित विकास और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि पौधारोपण के साथ-साथ पौधों की देखभाल, निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे वास्तव में पेड़ों में परिवर्तित हो सकें। अंत में उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर खर्च किए गए धन का सार्वजनिक लेखा-जोखा दिया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और हरियाणा को वास्तव में हरियाली से समृद्ध बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि केवल घोषणाओं से आगे बढकर धरातल पर परिणाम दिखाए जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके।

किसानों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के किसानों व आढ़तियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर त्वरित समाधान की मांग की है। उन्होंने मंडियों में लागू नई व्यवस्थाओं गेट पास, बायोमेट्रिक सत्यापन और समय-सीमा को किसानों के लिए जटिल व अव्यवहारिक बताया है, जिससे विशेषकर छोटे किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कटाई के व्यस्त समय में फोटो अपलोड व बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रियाएं अतिरिक्त बोझ बन रही हैं, वहीं सीमित समय-सीमा के कारण किसानों को अपनी उपज समय पर मंडी तक पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। कुमारी सैलजा ने पंजाब की तर्ज पर ओटीपी आधारित सरल प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, उन्होंने आढ़त दरों में मामूली बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए महंगाई के अनुरूप पुनर्समीक्षा की मांग की तथा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को पुनः खोलकर छूटे किसानों को पंजीकरण का अवसर देने की अपील की है।

संपादकीय नई बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था 2026: सैलरीड कर्मचारियों के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद ?

नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरूआत के साथ ही आयकर नियमों में कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर वेतनभोगी करदाताओं की जेब, बचत और निवेश रणनीति को प्रभावित करेंगे। बीते कुछ वर्षों से सरकार कर व्यवस्था को सरल बनाने और अधिक से अधिक लोगों को नए टैक्स सिस्टम की ओर आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे नए प्रावधानों के तहत टैक्स स्लैब, छूट, डिडक्शन और रिटर्न फाइलिंग से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसे में हर सैलरीड व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि इन बदलावों का उनके वित्तीय जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें किस टैक्स व्यवस्था का चुनाव करना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव नए टैक्स रिजीम को लेकर है, जिसे अब और अधिक आकर्षक बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है–ज्यादा से ज्यादा करदाता पुराने जटिल सिस्टम को छोड़कर सरल और पारदर्शी नई व्यवस्था को अपनाएं। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स दरें अपेक्षाकृत कम रखी गई हैं, लेकिन इसके बदले अधिकांश छूट और कटौतियों को समाप्त कर दिया गया है। वहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में 80सी, 80डी, एच आर ए जैसी कई लोकप्रिय छूटें अब भी उपलब्ध हैं, लेकिन टैक्स स्लैब अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि अब डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम नया रिजीम ही रहेगा। यानी यदि आप किसी विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपकी आय पर स्वतः ही नए टैक्स सिस्टम के अनुसार कर लगाया जाएगा। हालांकि, करदाता चाहें तो हर साल अपने फायदे के अनुसार पुराने और नए टैक्स सिस्टम में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यह लचीलापन सैलरीड क्लास के लिए राहत भरा है, क्योंकि वे अपनी आय, निवेश और खर्चों के आधार पर बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी राहत की खबर है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बरकरार रखा गया है, जिससे वेतनभोगी और पेंशनभोगी करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा। यह कदम सरकार के उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें वह नई व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और संतुलित बनाना चाहती है। इसके अलावा, नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कर का बोझ कम हो सके। इससे उन लोगों को विशेष लाभ होगा, जिनकी आय सीमित है और जो पहले ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते थे। हालांकि, जिन करदाताओं ने होम लोन, बीमा, पीएफ या अन्य टैक्स सेविंग योजनाओं में भारी निवेश किया है, उनके लिए पुराना टैक्स सिस्टम अब भी ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, और अन्य भत्तों से मिलने वाली छूट नए टैक्स सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं या यात्रा भत्ते का लाभ लेते हैं, उन्हें नए सिस्टम में इन छूटों का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में टैक्स प्लानिंग करते समय इन पहलुओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। निवेश आधारित छूटों जैसे कि धारा 80उ के तहत मिलने वाली कटौती भी नए टैक्स रिजीम में लागू नहीं होगी। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ, एलआईसी, ईएलएसएस जैसे विकल्पों में निवेश करते हैं। इसलिए यह निर्णय लेते समय कि कौन सा टैक्स सिस्टम चुना जाए, निवेश की आदतों का गहन विश्लेषण जरूरी हो जाता है। नई व्यवस्था में टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया है और प्री-फिल्ड रिटर्न की सुविधा को बेहतर बनाया गया है, जिससे करदाताओं को कम समय में और बिना ज्यादा तकनीकी जटिलताओं के रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए फॉर्म-16 और टीडीएस से जुड़े नियमों में भी पारदर्शिता बढ़ाई गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नियोक्ता द्वारा काटा गया टैक्स सही तरीके से सरकार तक पहुंचे और करदाता को रिफंड या अतिरिक्त भुगतान की स्थिति से बचाया जा सके। ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी करदाता की आय में साल के दौरान बदलाव होता है, तो वह अपने टैक्स सिस्टम के चयन को संशोधित कर सकता है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे आयकर बदलाव वेतनभोगी वर्ग के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आए हैं। जहां एक ओर नया टैक्स सिस्टम सरलता और कम दरों का लाभ देता है, वहीं दूसरी ओर यह पारंपरिक निवेश आधारित टैक्स बचत के रास्तों को सीमित करता है। ऐसे में हर करदाता को अपनी आय, खर्च, निवेश और भविष्य की वित्तीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। आयकर के ये नए नियम केवल गणना का तरीका नहीं बदलते, बल्कि यह आपके वित्तीय व्यवहार और बचत की रणनीति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय, अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और दोनों टैक्स व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें। सही चुनाव ही आपको अधिक बचत और बेहतर वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगा।

मूर्ख दिवसः तनाव भरे दौर में मुस्कान का पर्व

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

विश्वभर में 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'मूर्ख दिवस' साधारण दिन नहीं बल्कि हंसी, उल्लास और हल्के-फुल्के मजाक का ऐसा अवसर है, जो लोगों को रोजमर्रा की तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ पल के लिए राहत प्रदान करता है। इस दिन छोटे-बड़े, बच्चे-बुजुर्ग, सभी एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और बिना किसी दुर्भावना के हंसी-ठिठोली के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इस दिवस की सबसे खास बात यह है कि इसमें किए जाने वाले मजाक आमतौर पर हानिरहित होते हैं। लोग ऐसी कल्पनात्मक या मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर सामने वाला आसानी से विश्वास कर ले और बाद में जब सच्चाई सामने आए तो दोनों पक्ष हंसी में डूब जाएं। कई बार तो बड़े-बड़े बुद्धिमान और चतुर लोग भी इस दिन मजाक का शिकार बन जाते हैं, जिससे वातावरण और भी मनोरंजक हो उठता है।

यह परंपरा केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रही है बल्कि बड़े मीडिया संस्थान, प्रतिष्ठित कंपनियां और नामी ब्रांड भी इस दिन अनोखे और रचनात्मक 'प्रैंक्स' के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। इतिहास में कई रोचक उदाहरण मिलते हैं। 1957 में बीबीसी ने 'स्पेगेटी ट्री' की खबर प्रसारित की, जिसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में पेड़ों पर स्पेगेटी उगती है। हजारों लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। इसी तरह 1996 में बर्गर किंग ने 'लेफ्ट-हैंड व्हॉपर' बर्गर की घोषणा कर लोगों को चौंका दिया। डिजिटल युग में यह परंपरा और व्यापक हो गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसे मजाक कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी लोग सच्ची खबरों को भी 'अप्रैल फूल' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं।

मूर्ख दिवस की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। एक प्रचलित धारणा के अनुसार, प्राचीन समय में कई देशों में नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता था। जब कैलेंडर प्रणाली में बदलाव हुआ और नए साल की शुरूआत 1 जनवरी से होने लगी, तब भी कुछ लोग पुरानी परंपरा का पालन करते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए 1 अप्रैल को 'मूर्ख दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह परंपरा मनोरंजन का माध्यम बन गई।

भारतीय संस्कृति में भले यह परंपरा पश्चिम से आई हो लेकिन इसके मूल में निहित भावना (हंसी, आनंद और आपसी मेलजोल) भारतीय जीवन मूल्यों से भी मेल खाती है। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवनशैली में जहां लोगों के पास हंसने का समय कम हो गया है, वहां यह दिन एक सुखद अवसर प्रदान करता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मजाक की सीमा शालीनता और संवेदनशीलता के भीतर ही होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अपमान करने या नुकसान पहुंचाने वाला मजाक इस दिवस की भावना के विपरीत है। मूर्ख दिवस का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर हंसना और खुशियां बांटना है।

वास्तव में, शुद्ध हास्य न केवल मानसिक तनाव को कम करता है बल्कि आपसी संबंधों को भी मजबूत बनाता है। यह मन में सकारात्मकता और भाईचारे की भावना का संचार करता है। ऐसे में मूर्ख दिवस आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि मूर्ख दिवस केवल मजाक का दिन नहीं बल्कि जीवन में खुशियों के छोटे-छोटे पल तलाशने और उन्हें साझा करने का उत्सव है। यदि इसे शालीनता और सद्भाव के साथ मनाया जाए तो यह दिन सचमुच हंसी के अनमोल पलों से जीवन को सराबोर कर सकता है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

वैश्विक भारत : उद्योगों की रफ्तार, अर्थव्यवस्था का विस्तार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसकी गति, स्थिरता और विविधता ये तीनों ही उसे विशेष बनाती हैं। इस संबंध में सामने आए आर्थिक आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में दर्ज प्रगति इस व्यापक आर्थिक मजबूती का स्पष्ट संकेत है।

फरवरी 2026 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी के 4.8 प्रतिशत से अधिक है। कहना होगा कि यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में निरंतरता और विस्तार का प्रमाण है। इस वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा, जिसने छह प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। चूंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 75 प्रतिशत है, इसलिए इसका मजबूत प्रदर्शन पूरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को गति देता है।

वस्तुतः मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की यह प्रगति आज कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि को तो दर्शाती ही है, साथ में रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे युवा देश में, जहां हर वर्ष लाखों छात्र इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहां यह क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम बनता जा रहा है। फरवरी 2026 में मैन्युफैक्चरिंग के 23 उद्योग समूहों में से 14 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होना इस क्षेत्र की व्यापक मजबूती को दर्शाता है।

विशेष रूप से बुनियादी धातु, मोटर वाहन और मशीनरी एवं उपकरण जैसे क्षेत्रों में दोहरे अंकों की वृद्धि यह संकेत देती है कि भारत का औद्योगिक ढांचा अब अधिक परिपक्व और प्रतिस्पर्धी हो रहा है। बुनियादी धातु क्षेत्र में वृद्धि से निर्माण और अवसंरचना को बल मिलता है, जबकि ऑटोमोबाइल और मशीनरी क्षेत्र कृषि, परिवहन और उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। खनन और बिजली क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं हैं। फरवरी में खनन क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ये दोनों क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों की रीढ़ माने जाते हैं और इनमें वृद्धि का अर्थ है कि उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल और ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

इसके अलावा उपयोग-आधारित वर्गीकरण के आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन को उजागर करते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि यह दर्शाती है कि उद्योगों में निवेश बढ़ रहा है। मशीनों और उपकरणों का अधिक उत्पादन इस बात का संकेत है कि उद्योग विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भविष्य में उत्पादन, आय और रोजगार में और वृद्धि होगी।

इसी प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर और टीवी के उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि देश में मांग का स्तर बढ़ रहा है। यह बढ़ती आय, मध्यम वर्ग के विस्तार और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। जब उपभोक्ता खर्च बढ़ता है, तब यह पूरे आर्थिक चक्र को गति देता है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार सृजित होते हैं और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

यहां उल्लेखित है कि भारत की आर्थिक मजबूती का एक अन्य प्रमुख आधार सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में किया जा रहा भारी निवेश है। राजमार्गों, बंदरगाहों और रेलवे परियोजनाओं में लगातार बढ़ते निवेश के कारण अवसंरचना और निर्माण सामग्री क्षेत्र में फरवरी में 11.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। निश्चित ही यह उस दीर्घकालिक दृष्टि का परिणाम है, जिसके तहत सरकार देश को एक मजबूत लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रदान कर रही है।

इन परियोजनाओं का प्रभाव बहुआयामी है। एक ओर ये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करती हैं, वहीं दूसरी ओर उद्योगों के लिए लागत कम करती हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती हैं। बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क से माल परिवहन तेज और सस्ता होता है, जिससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। यदि व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत की अर्थव्यवस्था कई अन्य सकारात्मक संकेत भी दे रही है। देश की जीडीपी वृद्धि दर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक भी भारत को आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का प्रवाह लगातार बना हुआ है, जो वैश्विक निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'पीएलआई (उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन)' जैसी योजनाओं ने मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को नई दिशा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ में देखने में आ रहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था भी भारत की ताकत का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे प्लेटफॉर्म ने लेन-देन को सरल और पारदर्शी बनाया है। इससे न सिर्फ वित्तीय समावेशन बढ़ा है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी नई ऊर्जा मिली है।

महंगाई पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन भी भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाते हैं। सरकार द्वारा संतुलित राजकोषीय नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव फिर भी यहां अच्छी बात यह है कि भारत ने अपनी नीतिगत दृढ़ता और आंतरिक मांग के बल पर इनका प्रभाव सीमित रखा है।

अंततः, फरवरी 2026 के भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आंकड़े सिर्फ एक महीने की उपलब्धि न होकर यह उस निरंतर प्रयास और नीति-निर्माण का परिणाम हैं, जोकि भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की गति, पूंजीगत निवेश में वृद्धि, उपभोक्ता मांग का विस्तार और अवसंरचना पर फोकस, कहना होगा कि ये सभी मिलकर आज एक ऐसे आर्थिक परिदृश्य का निर्माण कर रहे हैं, जोकि आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्तियों में स्थापित कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके विकास की दिशा भी फिलहाल सुदृढ़ और टिकाऊ है।

आज का राशिफल

मेषः आज आपको किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। व्यापार में अपेक्षित लाभ मिलने से संतोष रहेगा। हालांकि परिवार में झिझक के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः राजनीति से जुड़े लोगों को आज मजबूत जनसमर्थन मिल सकता है। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और आप अपनों के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। घर में मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः आज आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है। अनजान लोगों पर भरोसा करने से बचें। गलत फैसलों के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है। विवादों को बातचीत से सुलझाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेवजह की बहसों में समय न गंवाएं, इससे नुकसान हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नई योजनाओं की शुरूआत के लिए दिन अनुकूल है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः करियर को लेकर मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है। किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। पढ़ाई और ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। बिना पूरी जानकारी के किसी बात पर प्रतिक्रिया न दें। पड़ोसियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम रखें। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः दाम्पत्य जीवन में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। व्यापार विस्तार के लिए दिन अच्छा है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में हल्की परेशानियां आ सकती हैं। परिवार से जुड़े विवादों को सुलझाने का सही समय है। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः जीवनसाथी की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। हृदय संबंधी रोगियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शुभचिंतकों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः आज आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। घर में धार्मिक माहौल रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। रिश्तेदारों से सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों के साथ व्यवहार मधुर रखें। *(सिटी दर्पण)*

धनुः आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे होने से खुशी मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपकी प्रबंधन क्षमता की सराहना होगी। दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

मकरः जीवनसाथी को आप पर गर्व महसूस होगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालने से बचें। कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियां दूर होंगी। विद्वानों और अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः आज आमदनी में कमी आ सकती है और काम में बाधाएं आ सकती हैं। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। कुछ कड़वे अनुभव मिल सकते हैं। अहंकार के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपने मन की हर बात दोस्तों से साझा करने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

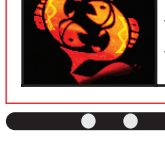

मीनः आज आपके फैसलों की सराहना होगी। विवाह से जुड़ी अड़चनें दूर हो सकती हैं। समाज में सम्मान बढ़ेगा। प्रेमी युगल के लिए दिन खास रहेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और घर के लिए खरीदारी भी कर सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

महिला सुरक्षा का सही रास्ता क्या है?

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या महिलाओं को दी गई आधुनिक स्वतंत्रता वास्तव में उनके लिए लाभकारी है या उन्हें शोषण के अधिक जोखिम में डाल रही है। हाल की घटनाओं और उन पर समाज की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह बहस फिर तेज हो गई है। कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता ही उनके शोषण का कारण बन रही है, जबकि अन्य इसे एक संकीर्ण और गलत दृष्टिकोण मानते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि इस विषय को भावनाओं के बजाय तर्क, तथ्यों और संतुलित दृष्टि से समझा जाए।

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शोषण का मूल कारण क्या है। क्या वास्तव में किसी महिला का पढ़ा-लिखा होना, आत्मनिर्भर होना या स्वतंत्र रूप से जीवन जीना उसके शोषण का कारण बन सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है- नहीं। शोषण का कारण हमेशा उस व्यक्ति की मानसिकता होती है जो अपराध करता है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल उसी व्यक्ति की होती है। इसे महिला स्वतंत्रता या उसके व्यवहार से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि यह पीड़िता को ही दोषी ठहराने जैसा है।

समाज में एक धारणा यह भी है कि यदि महिलाएं पिता, भाई या पति की निगरानी में रहें तो वे अधिक सुरक्षित रहती हैं। यह विचार पारंपरिक सोच से उत्पन्न हुआ है, जहां सुरक्षा और नियंत्रण को एक ही माना गया। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां महिलाओं के साथ शोषण उनके परिचितों या परिवार के भीतर ही हुआ है। इसका अर्थ यह है कि केवल निगरानी या नियंत्रण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सुरक्षा का संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने से नहीं बल्कि समाज में न्याय, कानून और जागरूकता की मजबूती से है।

यह भी कहा जाता है कि महिलाएं स्वभाव से भावुक होती हैं और इसी कारण वे आसानी से किसी के प्रभाव में आ जाती हैं। हालांकि यह आंशिक रूप से सही हो सकता है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक अभिव्यक्त होती हैं लेकिन इसे उनकी कमजोरी मान लेना बड़ी भूल है। भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला। असल समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं का गलत फायदा उठाता है। इसलिए समाधान यह नहीं है कि महिलाओं की भावनाओं को दबा दिया जाए या उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए बल्कि यह है कि समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो दूसरों का शोषण करते हैं।

आधुनिक समाज में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अपने निर्णय लेने का अधिकार मिला है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है, जिसने उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं। स्वतंत्रता का सही उपयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह केवल महिलाओं पर ही नहीं, बल्कि पुरुषों पर भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वतंत्रता ही गलत है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग और स्वतंत्रता स्वयं- दोनों में अंतर समझना आवश्यक है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पहले के समय में महिलाएं अधिक सुरक्षित थीं क्योंकि वे घर की चारदीवारी में रहती थीं। लेकिन यह धारणा भी पूरी तरह सही नहीं है। उस समय भी महिलाओं के साथ अन्याय और शोषण होता था लेकिन वे आवाज नहीं उठा पाती थीं। आज के समय में कम-से-कम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं और न्याय की मांग कर सकती हैं। यह बदलाव समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

रेप और अन्य अपराधों के बढ़ते आंकड़े निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। लेकिन इनका कारण महिलाओं की स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपराधियों की मानसिकता, कानून का कमजोर क्रियान्वयन और समाज में व्याप्त गलत सोच है।

यदि किसी समस्या का समाधान खोजना है तो उसके वास्तविक कारणों को समझना होगा। महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करना समस्या का समाधान नहीं है बल्कि यह एक तरह से समस्या से भागने जैसा है।

इसके विपरीत, हमें ऐसे समाज की कल्पना करनी चाहिए जहां महिलाएं सुरक्षित भी हों और स्वतंत्र भी। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले, शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता और सम्मान के मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति का सम्मान करना जरूरी है। दूसरा, कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि अपराधियों को जल्द और सख्त सजा मिल सके। तीसरा, महिलाओं को आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकें।

इसके अलावा, मीडिया और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करना या उनके चरित्र पर सवाल उठाना बंद करना होगा। समाज को यह समझना होगा कि महिला की गरिमा उसके कपड़ों, उसके व्यवहार या उसके निर्णयों से नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व से जुड़ी होती है।

अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा- दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसी एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना गलत दृष्टिकोण है। हमें ऐसा संतुलन बनाना होगा, जहां महिलाएं अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग कर सकें और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण का डर न हो।

समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उसमें हर व्यक्ति- चाहे वह पुरुष हो या महिला-सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। महिलाओं को 'निगरानी' में रखने के बजाय उन्हें 'सशक्त' बनाना ही सही दिशा है। यही एक ऐसा रास्ता है, जो न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकता है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

अब, अमेरिका और यूरोप की तरह पंजाब में महज 6 मिनट में पुलिस सहायता मिलेगी : भगवंत मान

ये वाहन सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किए जाएंगे; 112 डायल करने पर तुरंत सहायता सुनिश्चित करेंगे : मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
संगरूर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य भर में जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए संगरूर में 508 इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन (ईआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तर्ज पर महज छह मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वाहन डायल-112 सेवा के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किए जाएंगे, जो आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत सहायता सुनिश्चित करेंगे। यह कदम त्वरित और तकनीक-आधारित कानून प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान पुलिस वाहनों के लिए 327.70 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे न केवल पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ है बल्कि कानून-व्यवस्था भी मजबूत हुई है। साथ ही नशा तस्करों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, जिसका स्पष्ट उदाहरण टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपने दूसरे सबसे बड़े प्लांट की स्थापना के लिए किया जा रहा निवेश है।

संगरूर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब से नशे के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए आखिरी बार के रूप में नशे के कारोबार में शामिल लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीढ़ियों को बर्बाद किया है, उनके साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसे तत्वों को सबक सिखाना होगा और उनका सामाजिक बहिष्कार पंजाब को नशे की दलदल से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएगा।

सरकार की सख्त कार्रवाई को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने पहले ही नशे के व्यापार के खिलाफ कड़ा शिकंजा कस दिया है और ऐसे मामलों में सजा दर 87 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो किसी भी अन्य राज्य से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ युद्ध पंजाब में नशा नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हो रहा है, जिसके तहत सप्लाई चेन को तोड़कर और बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर इस अवैध कारोबार की रीढ़ तोड़ दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को जनसमर्थन के साथ जन आंदोलन में बदलने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत वर्तमान सरकार ने तस्करों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई पंजाब की युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए है और यह लगातार जारी रहेगी।

नशा आतंकवादझ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है और दुश्मन ताकतों का डटकर सामना करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार जमीनी स्तर तक पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों ही नहीं बल्कि थानों के एसएचओ स्तर तक भी वाहन उपलब्ध

कराए जा रहे हैं।

कानून-व्यवस्था और आर्थिक विश्वास के संबंध पर उन्होंने कहा कि किसी राज्य की कानून-व्यवस्था का सबसे बड़ा पैमाना वहां होने वाला निवेश होता है और टाटा स्टील का पंजाब में निवेश इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक बन रहा है और इसका श्रेय पंजाब पुलिस को जाता है, जिसने जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम किया है।

सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स शुरू की है। 1,597 प्रशिक्षित कर्मियों और 144 आधुनिक वाहनों के साथ यह फोर्स 4,200 किलोमीटर दुर्घटना-प्रभावित हाईवे पर तैनात है और इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48 प्रतिशत की कमी आई है। इस पहल की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सराहना की है। पुलिस के आधुनिकीकरण संबंधी बात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन पहल के तहत 508 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया जा रहा है। इससे डायल-112 फ्लीट में कुल वाहनों की संख्या बढ़कर 764 हो गई है। ये सभी वाहन जीपीएस ट्रैकर, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। बेहतर कुशलता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि डायल-112 पर प्रतिदिन लगभग 15,000 कॉल प्राप्त होती हैं, जिनमें से करीब 1,500 कॉल पर तुरंत वाहन भेजे जाते हैं और प्रतिक्रिया समय को 30-45 मिनट से घटाकर 13-14 मिनट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पुलिस कल्याण के लिए बहुत कम धन आवंटित किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने चार वर्षों में 327.69 करोड़ रुपये निवेश कर 2022 से अब तक 2,904 नए वाहन खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर पुलिस स्टेशन के पास कम से कम एक नया वाहन उपलब्ध है। विशेष इकाइयों को मजबूत करने संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनटीएफ को 22 महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन दिए गए हैं और महिलाओं की सुरक्षा तथा गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आगे ऐलान किया कि वर्ष 2026-27 में और वाहनों की खरीद के लिए 11.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने अतीत में आतंकवाद का कठिन दौर देखा है, लेकिन पुलिस बल के बलिदानों से राज्य में शांति स्थापित हुई है और आज पंजाब अपनी शांति के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद पंजाब पुलिस पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कृषि भूमि से गुजरने वाली हाई-टेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिससे किसानों और उनकी फसलों के लिए जोखिम कम होगा। भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक पंजाब पुलिस में 12,197 भर्तियां की जा चुकी हैं और आगे भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। मार्च 2026 में 1,746 कांस्टेबल और 3,298 नए पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

विपक्षी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कुछ नेता जनता को भ्रमित कर सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, लेकिन लोग उनके रिकॉर्ड से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिवंगत प्रकाश सिंह बादल ने भी कभी सुखबीर सिंह बादल को पूरी नेतृत्व जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर गोयल, डीजीपी गौरव यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत 4572 लाभार्थियों के लिए 23.32 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी के तहत आशीर्वाद योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जातियों के 4572 लाभार्थियों को 23.32 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहारा प्रदान करती है, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को बेटियों के विवाह के समय बड़ी राहत मिल रही है और सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती मिल रही है। डॉ. बलजीत कौर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर,

श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, एस.बी.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन के कुल 4572 लाभार्थियों को इस राशि का लाभ दिया गया है।

सामाजिक न्याय मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि से जिला बरनाला के 125, बठिंडा के 761, फरीदकोट के 87, फिरोजपुर के 266, श्री फतेहगढ़ साहिब के 155, गुरदासपुर के 164, होशियारपुर के 441, लुधियाना के 332 और मानसा के 441 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। इसी प्रकार जिला मोगा के 265, पटियाला के 126, पठानकोट के 221, रूपनगर के 293, एस.ए.एस. नगर के 166, एस.बी.एस. नगर के 83, संगरूर के 130, मालेरकोटला के 105 और तरनतारन के 411 लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह योजना अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों के लिए लागू है। उन्होंने कहा कि परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए और ऐसे परिवारों की अधिकतम दो बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए जन-केन्द्रित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

पंजाब भाजपा नेता गुरमीत सोढ़ी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की

एजेंसी
चंडीगढ़

भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के सीमावर्ती जिलों से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

सोमवार को इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। सोढ़ी ने शाह को सौंपे गए ज्ञापन में राज्य के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, पंजाब केवल एक सीमावर्ती राज्य नहीं है झ यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी मुख्य भूमिका निभाता है।

प्रतिनिधिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब सुरक्षा बाड़ के बाहर खेती करने वाले किसानों का मुद्दा भी उठाया।

सोढ़ी ने कहा, हजारों किसान दशकों से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते। इससे उन्हें लगातार अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। स्वामित्व प्रदान करना केवल नीतिगत निर्णय नहीं है; यह गरिमा और न्याय का प्रश्न है।

ज्ञापन में फिरोजपुर-फाजिल्का मार्ग का चौड़ीकरण (फोर-लेन) करने और राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की भी मांग की गई।

सोढ़ी ने कहा, यह मार्ग नागरिकों और रक्षा दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस सड़क को अपग्रेड करना निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने और लॉजिस्टिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

संक्षिप्त-समाचार

दुनियाभर में ट्रूकॉलर यूजर्स की संख्या 500 मिलियन के पार पहुंची

चंडीगढ़। ट्रूकॉलर ने घोषणा की है कि दुनिया भर में उसके यूजर्स की संख्या 500 मिलियन के पार पहुँच गई है। यह लोगों के बीच संचार को भरोसेमंद बनाने के कंपनी के सफर में एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या लगातार काफी तेजी से बढ़ रही है, और केवल साल 2025 में ही 50 मिलियन से ज्यादा नए यूजर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। अकेले भारत में ही ट्रूकॉलर का उपयोग करने वालों की संख्या 350 मिलियन से ज्यादा हो गई है, और भारत के बाहर इसके यूजर्स की संख्या 150 मिलियन से ज्यादा है। इसकी वजह है यह है कि, आज दुनिया भर में अनचाही कॉल्स, स्पैम और धोखाधड़ी से सुरक्षा की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इस साल की शुरूआत में, दुनिया भर में भुगतान करके ट्रूकॉलर की सेवाओं का लाभ उठाने वाले सब्सक्राइबर्स की संख्या भी 4 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई, जिससे कंपनी की आमदनी का एक मुख्य जरिया और भी मजबूत हुआ है। इस मौके पर ट्रूकॉलर के सीईओ, ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि वैसे तो यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह उस दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ बयां करता है, जिसमें आज हम सब रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पैम, स्कैम और अनचाहे संचार से निपटने में मदद की जरूरत है। 500 मिलियन यूजर्स के आंकड़े से जाहिर है कि लोगों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। साथ ही इसे यह भी पता चलता है कि लोग अपने संचार को सुरक्षित बनाने के लिए लोग ट्रूकॉलर पर कितना भरोसा करते हैं। ट्रूकॉलर को लगातार और भी ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी और नई खूबियों के साथ मजबूत बनाना ही हमारा संकल्प है, जो यूजर्स को हर कॉल या मैसेज से पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी सुरक्षित रहने में मदद कर सके। आखिर में, हमारा लक्ष्य संचार का ऐसा माहौल तैयार करना है जो सभी के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो। अब हमारी निगाहें अगले पड़ाव पर टिकी हैं और हम 1 बिलियन यूजर्स तक पहुँचना चाहते हैं।

डॉ. अदिति, पूजा चौहान और तिलक बने आइकॉनिक विनर 2026

चंडीगढ़। रॉयल पार्क रिसॉर्ट में नॉर्थ इंडिया आइकॉनिक फैशन शो सीजन-2 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देशभर से आए उभरते और प्रोफेशनल मॉडल्स ने रैंप पर अपने हुनर और आत्मविश्वास का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस मेगा इवेंट का आयोजन प्रीति अरोड़ा एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मॉडलिंग वर्कशॉप, फैशन शो, प्रोफेशनल फोटोशूट, नेटवर्किंग सेशन और मॉडलिंग प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं, जिन्होंने प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजबीर सिंह भारतीय, पंचकूला जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, डॉ. सुनील बेनीवाल, सुमित गुप्ता, अमरजीत सिंह , अनीकेत, सरोज बाला, अवतार सिंह कल्सिया, स्वरणजीत कौर, कश्मीर कौर, योगिंदर अग्रवाल, जगजीत कालोन, प्रदीप सिंह हैप्प, गुरप्रीत कौर, सविता प्रींजा, बाबा सुखबीर सिंह, राजिंदर बजाज, अल्फाज सिंह तथा कलाकार सपना, माही और मनीषा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इवेंट को सफल बनाने में वरुण गुप्ता (हंगरू) एवं हंगरू फ्रेंचाइजी ओनर साहिल ने अहम भूमिका निभाई, जबकि दिनेश सरदाना ने भी सहयोग प्रदान किया। मीडिया कवरेज में हरियाणा न्यूज फ्लैश के एडिटर रमेश गिल्होत्रा और परख न्यूज चैनल की चीफ एडिटर सना का विशेष योगदान रहा। इस इवेंट की खास आकर्षण डॉ. अदिति बंसल रहीं, जिन्होंने मिस कैटेगरी में विजेता का खिताब हासिल कर अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया।

गैंगस्टरों ते वार का 70वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 521 स्थानों पर छापेमारी; 214 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक गैंगस्टरों ते वार मुहिम के 70वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के पहचाने गए और मैप किए गए 521 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। 70वें दिन पुलिस टीमों ने 214 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 18,056 हो गई है। इसके अलावा 70 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 126 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 3 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को 395वें दिन भी जारी रखते हुए आज 85 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3.2 किलोग्राम हेरोइन, 586 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 21,780 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 395 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 56,330 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत, पंजाब पुलिस ने आज 20 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया।

> **पुलिस टीमों ने 70 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की, 126 को पूछताछ के बाद रिहा किया**

आतंकवाद प्रभावित परिवारों की मांगों पर राज्यपाल द्वारा सकारात्मक विचार का आश्वासन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के आतंकवाद प्रभावित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन में भेंट कर अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए लंबित वित्तीय पैकेज जारी करने, शहीद पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देने तथा विशेष पारिवारिक पेंशन लाभों के विस्तार की मांग की। उन्होंने नागरिक पीड़ितों के विधवाओं और माता-पिता के लिए पेंशन बढ़ाने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में लिए गए नीतिगत निर्णयों को लागू करने, प्लॉट आवंटन और नियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों, विशेषकर रेड और व्हाइट कार्ड धारकों को रियायती या निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।

रोजगार से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने पात्रता शर्तों में ढील देकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। साथ ही, आतंकवाद के दौरान विस्थापित होकर बाद में पंजाब लौटे परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों के लिए पेंशन सहायता की भी मांग की गई।

राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों और विभागों के साथ इस विषय को उठाएंगे और सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से समीक्षा की जाए। राज्यपाल ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के कल्याण, पुनर्वास और सहयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

प्रतिनिधिमंडल में सतिंदरपाल सिंह सिद्धू; डॉ. बी.आर. हस्स्तिर; प्रिंस कुमार; रमन कुमार; जसकरण सिंह; मनजीत कौर; शिंदर कौर; चंचल मनहास; दर्शन कौर; जसबीर कौर; बलविंदर कौर; बीरो; बलबीर कौर; कुलविंदर कौर; वर्षा रानी; पवाना देवी; त्रिप्ता शर्मा; चरणजीत कौर; कश्मीर कौर; साविंदर कौर; रीता जुनेजा शामिल थे।

सुधारीकरण | **पंजाब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक सुधारों की घोषणा**

मंत्रिमंडल ने फ्रीहोल्ड और औद्योगिक आधारभूत ढांचे के प्रबंधन के लिए लीजहोल्ड संबंधी महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी: संजीव अरोड़ा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नीति में महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही फ्रीहोल्ड प्लॉट धारकों के लिए आवंटन के बाद की सेवाओं को व्यापक रूप से तर्कसंगत बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्र के भागीदारों के साथ व्यापक परामर्श और समूह मंत्रियों की सिफारिशों के बाद किए गए ये सुधार व्यापार करने की आसानी को और मजबूत करने तथा एक पारदर्शी, निवेशक-अनुकूल औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

मुख्य सुधार: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तबादला

मुख्य फैसलों पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा: केवल 5 प्रतिशत तबादला शुल्क निर्धारित किया गया है। 30 अप्रैल, 2026 तक किए गए तबादलों के लिए स्टांप ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट। जहां अन-अर्जित वृद्धि (अनअर्न्ड इंक्रीमेंट) की धारा लागू नहीं है, वहां खर्चों की छूट के माध्यम से महत्वपूर्ण राहत। विशेष मामलों में, बार-बार लगने वाले शुल्क के लिए एक ही शुल्क लागू किया गया है। कई सेवाओं के लिए वार्षिक नवीनीकरण खर्च बंद कर दिए गए हैं।

तुरंत तबादले को प्रोत्साहित करने और पुराने मुद्दों के निपटारे के लिए: लंबित तबादलों और परिवर्तन संबंधी मामलों का समयबद्ध निपटारा। तुरंत तबादलों के लिए एकमुश्त स्टांप ड्यूटी में छूट।

कागजी कार्रवाई को सरल बनाना: मॉर्टगेज लीज डीड्स के मामले में बैंक पत्र ही पर्याप्त है। अनअर्जित वृद्धि की धारा पर स्पष्टता।

लंबित औद्योगिक मुद्दों का निपटारा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया: जहां टाइटल दस्तावेजों में धारा मौजूद नहीं है, वहां कोई अन-अर्जित वृद्धि नहीं ली जाएगी। पारिवारिक तबादला, विरासत, या मृत्यु के मामलों में जहां

प्लॉट पहले ही नोटिफिकेशन से पहले फ्रीहोल्ड में बदल चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, इससे अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की गई है और उद्योगपतियों को अनुचित वित्तीय देयताओं से बचाया गया है।

कारोबार करने में आसानी संबंधी मुख्य सुधार

एक क्रांतिकारी कदम के रूप में: सेवाओं को अनिवार्य और वैकल्पिक श्रेणियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया। 18 सेवाओं को अनिवार्य से वैकल्पिक में बदला गया। नोटरीकृत हलफनामों को स्व-घोषणा से प्रतिस्थापित किया गया। स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए एस्टेट अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपे गए। श्री अरोड़ा ने कहा, इससे अनुपालन संबंधी बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम किया गया है और फ्रीहोल्ड तबादले को उद्योगों के लिए बेहद फायदेमंद बनाया गया है।

पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2026

मंत्रिमंडल ने औद्योगिक आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

1.एकीकृत और पारदर्शी आधारभूत ढांचा प्रबंधन

सभी औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए एक ही विधि।

कवरेज: औद्योगिक फोकल पॉइंट, औद्योगिक संपत्ति, औद्योगिक क्लस्टर (नोटिफाइड पार्कों से बाहर के स्थानों सहित)।

2. उद्योगों को बड़ी वित्तीय राहत

नगर निगम क्षेत्रों में सर्विस चार्जेस को संपत्ति कर में शामिल किया गया।

दोहरे कर को समाप्त किया गया।

नियमों को सरल बनाया गया और वित्तीय बोझ कम किया गया।

3. नवीन संग्रह विधि

पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड द्वारा सर्विस चार्जेस बिजली बिलों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे।

लाभ: नियमों में संशोधन, सहज और पारदर्शी संग्रह प्रणाली।

4.उद्योग-अनुकूल शासन

विशेष उद्देश्य वाहन बनाए जाएंगे:

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत।

उद्योगिक हिस्सेदारों के नेतृत्व में।

शासन ढांचा: उद्योगिक आबंटियों में से 7 सदस्यीय कार्यकारी समिति चुनी जाएगी, तालमेल और निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी।

स्पष्ट जवाबदेही और पेशेवर प्रबंधन।

5. मजबूत वित्तीय ढांचा

90% फंड → रखरखाव के लिए

10% फंड → आधारभूत ढांचे को अपग्रेड करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को

भविष्य के विकास के लिए अनिवार्य कॉर्पस फंड

कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक खर्चों पर सीमा

6. जवाबदेही और निगरानी

सरकार को अधिकार:

एसपीवी का ऑडिट और निगरानी

यदि आवश्यक हो तो खराब प्रदर्शन करने वाले एसपीवी को रद्द करना

उद्योग को सशक्त बनाना और पंजाब के विकास को मजबूत करना

संजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि ये महत्वपूर्ण सुधार हमारी सरकार के स्पष्ट विजन को दर्शाते हैं, जो उद्योगों को सशक्त बनाना, नियमों के बोझ को कम करना और एक आधुनिक, पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर औद्योगिक माहौल सृजित करना है। पंजाब देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेशक-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य बिंदु

उद्योगपतियों के लिए बड़ी वित्तीय राहत

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में सरल तबादला

कम नियम और तेज स्वीकृतियां

उद्योग-अनुकूल आधारभूत ढांचा प्रबंधन

कारोबार करने की सुविधा पर विशेष ध्यान।पंजाब का मतलब है कारोबार।

ईरान के इस्फहान शहर पर हमला, दुबई में विशाल टैंकर आग की लपटों से घिरा

इस्फहान के सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को बनाया गया निशाना

❍ हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर बरसाए ड्रोन

एजेंसी (हि.स.)

तेहरान/कुवैत सिटी/बेरुत/बगदाद

फोटोः हि.स.

अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऐतिहासिक शहर इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया है। इस शहर की आबादी लगभग 23 लाख है। यहां बदर मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। जोरदार धमाकों और आग की लपटों से आज सुबह तक आसमान में दहशत रोशन रही। इस बीच कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया है कि दुबई बंदरगाह पर विशाल तेल टैंकर 'अल-सलमी' पर ईरान के हमले के कारण आग लग गई है। कॉर्पोरेशन ने चेतावनी दी है कि इससे तेल फैल सकता है। उधर, हिजबुल्लाह ने इजराइली सेना पर हमलों का दावा किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने इस्फहान में हमले के कई वीडियो तैयार किए हैं। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह ईरान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां कपड़ा और इस्पात की मिलें हैं। यहां ईरान का महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र (नतंज) और सैन्य मिसाइल बनाने के कारखाने भी हैं। इसके कारण यह अकसर चर्चा में रहता है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल की मिसगाव अम बस्ती में एक सैन्य चौकी को निशाना बनाते हुए ड्रोन की बौछार कर दी। यही नहीं दक्षिणी लेबनान के अल-कंतारा और तैबेह कस्बों के बीच सड़क पर मौजूद एक इजराइली मर्कवा टैंक पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हमले में टैंक जल गया। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज का कहना है कि अमेरिकी-इजरायली सेनाओं ने बाबुल और अनबार प्रांतों में उनके दो ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। बाबुल प्रांत के जुर्फ अल-नस्र सेक्टर में 45वीं ब्रिगेड पर लगातार तीन हवाई हमले किए गए। एक और हमला अनबार प्रांत के पूर्व में अल-कर्मा सेक्टर में हुआ। इस हमले में 31वीं ब्रिगेड के ठिकाने को निशाना बनाया गया। उधर, कुर्द अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र में स्थित सुलेमानिया शहर को निशाना बनाकर किए गए दो हमलों को विफल कर दिया गया है।

यूएन अधिकारी मोहम्मद सफा का इस्तीफा, तेहरान पर संभावित परमाणु हमले को लेकर गंभीर चेतावनी

न्यूयॉर्क/तेहरान। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अधिकारी मोहम्मद सफा ने ईरान पर संभावित परमाणु हमले की आशंका जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि तेहरान पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। सफा ने अपने बयान में कहा कि ह्ललोग इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और आरोप लगाया कि लाखों आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली संभावित कार्रवाई की तैयारी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस जानकारी को सार्वजनिक करने के कारण उन्होंने अपना कूटनीतिक करियर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को निलंबित कर दिया ताकि वह किसी भी ऐसे कदम का हिस्सा न बनें, जिसे उन्होंने ह्लमानवता के खिलाफ अपराध बताया। सफा ने न्यूक्लियर विंटर' जैसी स्थिति की आशंका जताते हुए कहा कि समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सफा की यह टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दे सकती है।

लीबिया से ग्रीस जा रही प्रवासियों की नाव समुद्र में रास्ता भटकी, 22 की मौत

❍ इनमें 12 बांग्लादेश के

एजेंसी (हि.स.)

ढाका

फोटोः हि.स.

लीबिया से ग्रीस जा रही प्रवासियों की नाव समुद्र में रास्ता भटक गई। इस दौरान 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 युवा बांग्लादेश के नागरिक हैं। सुनामगंज के उपायुक्त मोहम्मद इलियास मिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार मानव तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करेगा।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सुनामगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजन सरकार ने बताया कि अब तक उन्होंने 12 नागरिकों की मौत की पुष्टि कर ली है। इनमें से छह लोग डेराई उपजिला के, पांच लोग जगन्नाथपुर उपजिला के और एक व्यक्ति दोराबाजार उपजिला का रहने वाला है। सुनामगंज के उपायुक्त मोहम्मद इलियास ने कहा कि इनके शव समुद्र से मिल गए हैं। 28 मार्च को बचाए गए 26 लोगों को ग्रीस के एक शिविर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस, परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद अब तक 12 मृतकों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। जान गंवाने वालों में मो. नूरुज्जमान सरदार मोयना (30), साजिदुर रहमान (28), साहन एहिया (25), मुजीबुर रहमान (38), तायक मिया, अबू फहीम, सोहनुर रहमान, शायेक अहमद, मो. नईम मिया, अमीनुर रहमान और मोहम्मद अली हैं।

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मानव तस्करों ने युवकों को 12 से 15 लाख टका के बदले इटली पहुंचाने का वादा करके फंसाया था। सबको सबसे पहले लीबिया ले जाया गया। उन्हें जबरदस्ती ठसाठस भरी नावों में बिठा दिया गया। पुलिस ने बताया कि ग्रीक कोस्टगार्ड ने 28 मार्च को 26 लोगों को बचाया। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। लीबिया में अस्थिरता का फायदा उठाकर मानव तस्कर गिरोह सक्रिय हैं, जो दक्षिण एशियाई देशों के युवाओं को निशाना बनाते हैं। अक्सर इन नावों में नेविगेशन के पर्याप्त उपकरण और लाइफ जैकेट नहीं होते। जब नाव गहरे समुद्र में रास्ता भटक जाती है, तो भोजन और पानी की कमी के साथ-साथ खराब मौसम प्रवासियों के लिए काल बन जाता है।

पाकिस्तान की डॉ. फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बहाल

एजेंसी (हि.स.)

इस्लामाबाद

फोटोः हि.स.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की अंतरिम जमानत 100,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर बहाल कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने की। पीठ ने आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया।

दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान डॉ. फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में पेश हुईं। इस बीच अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने साफ किया कि वह अपनी बहन के मामले में शामिल नहीं हैं। वकील नईम बुखारी ने दलील दी कि डॉ. फजीला तीन बार अदालत में पेश हुई थीं। एक बार वह पेश नहीं हो सकीं और तीन दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया, इसके बावजूद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अंतरिम जमानत बहाल कर दी। उल्लेखनीय है कि संघीय जांच एजेंसी ने डॉ. फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके 22 बैंक खातों में लगभग 25 अरब रुपये का टर्नओवर हुआ, जबकि उनकी घोषित सालाना आय केवल 400,000 रुपये से 600,000 रुपये के बीच थी। डॉ. फजीला अब्बासी प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ और सौंदर्य चिकित्सक हैं। वे इस्लामाबाद और दुबई में अपने क्लीनिक संचालित करती हैं। उन्हें पाकिस्तान में लेजर तकनीक और एडवांस्ड एस्थेटिक प्रक्रियाओं (जैसे डर्मल फिलर्स) को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी का निधन

पारामारिबो। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी का सोमवार को अचानक निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। उनके निधन की पुष्टि देश की वर्तमान राष्ट्रपति जेनिफर सिमंस ने की। संतोखी ने वर्ष 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के अध्यक्ष भी थे और इससे पहले 2005 से 2010 के बीच देश के न्याय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। राष्ट्रपति जेनिफर साइमंस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि संतोखी का सार्वजनिक जीवन में योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। उन्होंने देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय सेवाएं दीं। हालांकि, उनके निधन के कारणों का तत्काल खुलासा नहीं किया गया है। संतोखी के अचानक निधन से देश में शोक की लहर है और राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।

किशनगंज डीएसपी और सहरसा डीआरडीए निदेशक के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

एजेंसी (हि.स.)

पटना

फोटोः हि.स.

बिहार में किशनगंज जिले के डीएसपी गौतम कुमार के 6 ठिकाने सहित सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के भी छह ठिकानों पर मंगलवार सुबह से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छापामारी चल रही है। किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार ने अपने महिला मित्र शगूफ्ता खातून के नाम कई भूखंड खरीदे, फिर महिला मित्र ने डीएसपी के बेटों को सभी भूखंड गिफ्ट कर दिए।

दूसरी ओर सहरसा में डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार के सहरसा एवं मुज्जफरपुर स्थित छह ठिकानों पर छापामारी चल रही है। इन पर आय से 78 प्रतिशत से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज किया है। आर्थिक अपराध इकाई को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज किया और निगरानी की स्पेशल कोर्ट से तलाशी का आदेश लिया। इसके बाद दोनों भ्रष्ट अधिकारियों के 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी की कार्यवाई की जा रही है। जांच में आर्थिक अपराध इकाई को किशनगंज में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर तैनात गौतम कुमार के खिलाफ आय से एक करोड़ 94 लाख नौ हजार दो सौ चवालीस रुपए अधिक सम्पति अर्जित करने के साक्ष्य मिले, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 60.27 प्रतिशत अधिक है।

इस क्रम में आज सुबह गौतम कुमार के पटना, पूर्णिया, किशनगंज अवस्थित कुल 06 ठिकानों पर अलग-अलग टीम द्वारा तलाशी कार्यवाई शुरू की गई है। वहीं ईओयू की टीम ने वैभव कुमार, निदेशक, डीआरडीए, सहरसा के विरूद्ध कुल 2,41,14,000 (दो करोड़ एकतालीस लाख चौदह हजार) रुपये आय से अधिक सम्पति अर्जन करने का साक्ष्य पाया गया है, जो उनके ज्ञात आय से लगभग 78.03 प्रतिशत से अधिक है। इसको लेकर वैभव कुमार के सहरसा एवं मुजफ्फरपुर अवस्थित कुल 06 ठिकानों पर अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं।

संक्षिप्त-समाचार

बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। मंगलवार को जारी की गई इस सूची के साथ ही 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए पार्टी अब तक 287 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अब केवल सात सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होना शेष रह गया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की स्वीकृति के बाद जारी इस सूची में कुल 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें सिताई (अनुसूचित जाति) से आशुतोष वर्मा, नाटाबाड़ी से गिरिजा शंकर राय, बागदा (अनुसूचित जाति) से सोमा ठाकुर, मोगराहाट पूर्व (अनुसूचित जाति) से उत्तम कुमार बनिक, फलता से देबांशु पांडा, सोनारपुर उत्तर से देबाशीष धर, चौरंगी से संतोष पाठक, हावड़ा दक्षिण से श्यामल हाटी तथा पांचला से रंजन कुमार पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा चांदीपुर से डॉ. पीयूष कांति दास, गड़बेता से प्रदीप लोढ़ा, मेमारी से मानव गुहा तथा बाराबनी से अरिजीत राय को उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही पार्टी ने एक सीट पर अपने पहले घोषित उम्मीदवार में बदलाव करते हुए मयनागुड़ी (अनुसूचित जाति) से दलीम राय को नया उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होंगे और चार मई को मतगणना होनी है।

घाटी से अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव बरामद

कोडरमा। कोडरमा थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह कोडरमा घाटी के मेघातरी स्थित पैरी माइंस के समीप सड़क किनारे जंगल से एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया है। मृत महिला की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। लोगों ने आशंका जताया है कि महिला की अन्यत्र हत्या कर शव को बोरे में डालकर किसी वाहन से वहां फेंक दिया गया। मंगलवार की सुबह मेघातरी के कुछ ग्रामीण जब सड़क किनारे टहल रहे थे, तो उन्हें प्लास्टिक के बोरे में कुछ दिखाई पड़ा। जब वे लोग नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां महिला का पैर बोरे से बाहर निकला हुआ था। जिसके बाद उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को वहां इकट्ठा कर लिया। वहीं इसकी जानकारी कोडरमा पुलिस को भी दी। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। उल्लेखनीय कि अभी एक महीने पूर्व ही कोडरमा थाना क्षेत्र के ही जेजे कॉलेज के ठीक सामने होली फैमिली अस्पताल के बाउंड्री वॉल के अंदर इसी प्रकार से एक अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव बरामद किया गया था। महिला का सिर भी गायब था, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक बार फिर इस प्रकार शव के मिलने से लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में टीवीके प्रमुख विजय के खिलाफ केस दर्ज

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अभिनेता और टीवीके पार्टी के नेता विजय के समेत लगभग पांच सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेरावल्लूर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में सोमवार को कोलाथूर में प्रचार के दौरान प्रचार के दौरान यातायात में बाधा डालने और अधिक लाउडस्पीकर के प्रयोग करने का आरोप लगा गया है। दरअसल, विजय को प्रचार के दौरान केवल पांच लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन चुनाव अधिकारी को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए 30 लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया, जिससे आम जनता को असुविधा हुई। इसके अलावा, पांच हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने और एंबुलेंस को रास्ता न देने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। चुनाव अधिकारियों की शिकायत के आधार पर विजय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सराफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार शुरूआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में मामूली तेजी का रुख नजर आ रहा है। वहीं चांदी के भाव में मंगलवार कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने की कीमत में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना मंगलवार 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना मंगलवार 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,36,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु मंगलवार शुरूआती कारोबार कै दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार के भाव पर यानी 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में मंगलवार 24 कैरेट सोना 1,48,420 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना मंगलवार 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,35,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

लखनऊ के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना मंगलवार 1,48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,36,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,35,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,48,420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,36,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,35,910 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

राहुल गांधी ने पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में सोमवार सुबह टहलने निकले सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर वीके जोशी की गोली लगने से मौत को लेकर उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में कहा कि दिनदहाड़े हुई यह हत्या साफ बताती है कि उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरहद पर देश की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाले ही आज अपने शहर में असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिक और कई समुदाय डर के साये में जीने को मजबूर हैं। भाजपा शासन में अपराधी बेखौफ और सुरक्षित हैं। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा उत्तराखंड आज हिंसा, हत्या और भय से घिरा हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजपुर थाना क्षेत्र के जोहड़ी गांव में सोमवार सुबह करीब 6:50 बजे यह घटना हुई। मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के बीच गाड़ी को पास न देने पर विवाद हुआ। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा कर टायरों पर फायरिंग की। उसी दौरान एक गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे पूर्व ब्रिगेडियर को जा लगी। घायल ब्रिगेडियर वीके जोशी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

असम चुनाव के लिए भाजपा का 'संकल्प पत्र' 3 लाख से अधिक लोगों के सुझावों से तैयार: सोनोवाल

एजेंसी (हि.स.)

गुवाहाटी

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता सबानंद सोनोवाल ने कहा कि असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का 'संकल्प पत्र' बड़े पैमाने पर लोगों से सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया गया है। इसमें तीन लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना 'संकल्प पत्र' (मैनिफेस्टो) जारी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सबानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में सोनोवाल ने घोषणापत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे राज्य में लोगों से सीधे उनकी राय जानने के लिए उनके पास पहुंचे। हम असम के हर हिस्से में लोगों के पास गए। घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए कि अगले कार्यकाल में क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद नीतिगत प्राथमिकताओं को लोगों की राय के आधार पर तय करना था। उनके मुताबिक 3 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि पार्टी के एक बार फिर से सत्ता में आने पर वह इन्हीं सुझावों पर भरोसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज के आधार पर हम तीसरे कार्यकाल में काम करेंगे। चुनावी संभावनाओं के बारे में बात करते हुए सोनोवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के मजबूत प्रदर्शन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं कि हम अपने सहयोगियों के साथ 100 के आंकड़े के करीब हैं, जो 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में पार्टी के लक्ष्य की ओर इशारा करता है।

इतिहास

आरबीआई की स्थापना से लेकर एप्पल की शुरूआत का खास दिन

बैंकिंग जगत में भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीक की दुनिया में वैश्विक क्रांति की शुरूआत

एजेंसी (हि.स.)

फोटोः हि.स.

इतिहास में 01 अप्रैल की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जानी जाती है। इस दिन भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना हुई, वहीं तकनीकी दुनिया में क्रांति लाने वाली एप्पल की भी शुरूआत इसी दिन हुई थी। भारत में 01 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो देश की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के रूप में कार्य करता है। बाद में 01 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई देश की मौद्रिक नीतियों का संचालन करता है और वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। वहीं, 01 अप्रैल 1976 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की। शुरूआती दौर में कंपनी का नाम एप्पल कम्प्यूटर रखा गया था, जिसे बाद में 09 जनवरी 2007 को बदलकर एप्पल आईएनसी कर दिया गया। इसी वर्ष स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश किया, जिसने मोबाइल तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। आज एप्पल राजस्व के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है और स्मार्टफोन निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। इस तरह 01 अप्रैल का दिन आर्थिक और तकनीकी दोनों ही क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसने दुनिया को नई दिशा देने वाले बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया।

जन्म

1891 - प्राण कृष्ण पारिजा - भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। 1911 - केदारनाथ अग्रवाल- प्रगतिशील काव्य-धारा के एक प्रमुख कवि एवं लेखक। 1911 - फौजा सिंह- एथलीट। 1927 - जोगेश दास - असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। 1936 - जबीन जलील - हिन्दी सिनेमा की 1950 और 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। 1937 - मोहम्मद हामिद अंसारी - भारत के 13वें उपराष्ट्रपति 1941 - अजित वाडेकर - भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। 1952 - ओ. पी. शर्मा - भारत के प्रसिद्ध जादूगर थे। 1986 - वीरेन्द्र सिंह - भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान हैं। 1989 - केशव बलिराम हेडगेवार - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं क्रांतिकारी थे।

निधन

1907 - गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी - आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक तथा इतिहासकार। 1977 - सीरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील थे जिन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार की थी। 2010 - हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स, पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) के युग की शुरूआत करने वाले। 2015 - कैलाश वाजपेयी, हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार।

महत्वपूर्ण अवसर

■ ओडिशा स्थापना दिवस (उत्कल दिवस)- उड़ीसा के अलग राज्य बनने के उपलक्ष्य में। ■ मूर्ख दिवस।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1582 - फ्रांस में इस दिन को मूर्ख दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत हुई। 1793 - जापान में उनसेन ज्वालामुखी फटा, जिसकी वजह से करीब 53,000 लोगों की मौत हो गई। 1839 - कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बीस बिस्तरों के साथ शुरू किया गया। 1889 - हिंदू का दैनिक अखबार के तौर पर प्रकाशन शुरू। 20 सितंबर 1888 से प्रकाशित इस अखबार को अब तक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा था। 1912 - भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1930 - विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1935 - भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। 1936 - भारत के उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई, जो कि पहले कलिंग या उत्कल के नाम से जाना जाता था। 1969 - तारापुर में देश के पहले परमाणु बिजली घर ने काम करना शुरू किया। 1973 - भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए 'टाइगर बचाओं' अभियान चलाया गया। 1976 - टेलिविजन के लिए एक पृथक निगम की स्थापना की गई, जिसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1976 - स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐपल कंपनी की स्थापना की। 1979 - ईरान मुस्लिम गणराज्य घोषित। 1996 - बैंक ऑफ टोकियो और मित्सुबिशी बैंक के विलय से बना विश्व का सबसे बड़ा बैंक न्यू बैंक आफ टोकियो-मित्सुबिशी ने अपना कार्य आरम्भ किया। 1997 - मार्टिना हिंगिस टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र की नंबर एक महिला खिलाड़ी बनीं। 1999 - मध्य पूर्व के विशेषज्ञ, चिन्तक और आलोचक प्रो. एडवर्ड डब्ल्यू. सेड को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने न्यूयार्क में आयोजित एक समारोह में डि-लिट् की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 2001 - यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविच का आत्मसमर्पण। 2004 - गूगल ने जीमेल का ऐलान किया। 2004 - मुल्तान में भारत ने पाक धरती पर पहली जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान को एक पारी और 52 रनों से हराया। 2005 - नेपाल में आपातकाल लागू होने के बाद बंदी बनाये गये गिरिजा प्रसाद कोइराला के साथ 285 राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। 2006 - रियो डी जिनेरियो में विमान दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु। 2007 - नेपाल की अंतरिम सरकार में 5 माओवादी नेता शामिल। 2008 - मुम्बई की विशेष अदालत ने 47 करोड़ रुपये के शेयर घोटाले के मामले में केतन पारेख व हितेन दलाल सहित पाँच को एक-एक साल की सजा सुनाई। 2008 - अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने एक नया इमेजिंग सिस्टम तैयार किया। 2008 - दक्षिण अमेरिका के पेरु में 4000 साल पुराना सोने का हार मिला। 2010 - राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का ब्योरा दर्ज करने के साथ 15वीं जनगणना का काम शुरू हो गया। इसके तहत आबादी का बायोमीट्रिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा।

केवल पारंपरिक केंद्रों तक सीमित न रहें टेस्ट मैच: सौरव गांगुली

पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने किया बीसीसीआई की रोटेशन नीति का समर्थन

कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े मैदानों के साथ गुवाहाटी और रांची में भी क्रिकेट का विस्तार जरूरी

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आगामी घरेलू सत्र के लिए टेस्ट मैचों के केंद्रों के चयन को लेकर जारी बहस के बीच पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बोर्ड के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। कोलकाता में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान गांगुली ने स्पष्ट किया कि हालांकि ईडन गार्डन्स जैसे ऐतिहासिक मैदानों पर टेस्ट मैच देखना सुखद होता है, लेकिन खेल के विकास के लिए नए केंद्रों जैसे गुवाहाटी और रांची में टेस्ट मैचों का आयोजन अनिवार्य है। गांगुली की यह प्रतिक्रिया बीसीसीआई द्वारा पिछले सप्ताह घोषित 2026-27 के घरेलू सत्र के कैलेंडर के बाद आई है।

बोर्ड ने आगामी प्रतिष्ठित 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' (भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया) के टेस्ट मैचों को कोलकाता या मुंबई जैसे पारंपरिक केंद्रों के बजाय नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया है। स्पोर्ट्सस्टार की पुस्तक 'मिरेकल एट ईडन' के विमोचन के अवसर पर गांगुली ने कहा कि एक पूर्व खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशासक के रूप में उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि ईडन गार्डन्स पर बड़े मैचों का आयोजन हो। हालांकि, उन्होंने रोटेशन नीति का बचाव करते हुए कहा कि ईडन ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, टी20 विश्व कप के मैचों और अब आईपीएल की मेजबानी की है। गांगुली ने जोर देकर कहा, 'हमें यह समझना होगा कि भारत के अन्य हिस्सों में भी विश्व स्तरीय स्टेडियम और सुविधाएं मौजूद हैं। चेन्नई, गुवाहाटी और रांची जैसे केंद्रों पर टेस्ट क्रिकेट को जाते देखना एक सकारात्मक संकेत है। खेल के प्रसार के लिए यह जरूरी है कि हर राज्य के दर्शकों को टेस्ट क्रिकेट देखने का मौका मिले।' गौरतलब है कि गुवाहाटी नवंबर 2025 में ही टेस्ट केंद्र बना है और एक साल के भीतर वहां दूसरा टेस्ट आयोजित होने जा रहा है। बीसीसीआई के नए कैलेंडर के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज 21 जनवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच खेली जाएगी। वहीं, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े केंद्रों को इस बार सीमित ओवरों के मैचों की जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ सौरव गांगुली बोर्ड की नई नीति के पक्ष में दिखे, वहीं भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर वेंकटपति राजू ने थोड़ा अलग रुख अपनाया। राजू का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट का असली आकर्षण कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसे पांच पारंपरिक केंद्रों में ही निहित है। उनके अनुसार, इन मैदानों का एक अपना ऐतिहासिक महत्व और आकर्षण है, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए। हालांकि, गांगुली का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नए स्टेडियमों में भी टेस्ट क्रिकेट को उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए। यह पहली बार है जब गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद घरेलू सत्र के केंद्रों के आवंटन पर खुलकर अपनी बात रखी है। कार्यक्रम के दौरान गांगुली ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि ईडन गार्डन्स पर 2001 की उस ऐतिहासिक टीम के खिलाड़ियों को एकजुट करने की योजना बनाई जा रही है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार जीत दर्ज की थी।

फिडे कैंडिडेट्स 2026, राउंड 2: प्रज्ञानानंद ने ड्रॉ खेलकर संयुक्त बढ़त बरकरार रखी

दिव्या-वैशाली का मुकाबला भी ड्रॉ

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फिडे कैंडिडेट्स 2026 के दूसरे राउंड में भारत के ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने शानदार लय बरकरार रखते हुए ड्रॉ खेला और अंक तालिका में संयुक्त बढ़त बनाए रखी। उन्होंने चीन के वेई यी के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेला। इससे पहले प्रज्ञानानंद ने पहले राउंड में उच्च रैंकिंग वाले अनिश गिरी को हराकर शानदार शुरूआत की थी।

वेई यी ने मुकाबले की शुरूआत पेट्रोफ डिफेंस से की, जिससे खेल की संरचना संतुलित और जटिल हो गई। प्रज्ञानानंद ने अपने रुख और छोटे मोहरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह के आक्रमण को निष्क्रिय कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में उच्च स्तर की सटीकता दिखाई और समय नियंत्रण के करीब पहुंचते-पहुंचते मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया।

महिला वर्ग में ऑल-इंडियन मुकाबले में दिव्या देशमुख और आर वैशाली के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जो अंततः ड्रॉ पर खत्म हुआ। दिव्या ने ठोस रणनीति अपनाते हुए अपने नाइट के इर्द-गिर्द खेल को आगे बढ़ाया और वैशाली पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि, इस मुकाबले की सबसे बड़ी बात वैशाली की समय की स्थिति रही।

वह जल्दी ही समय के दबाव में आ गईं और उन्हें पहले सत्र के अंतिम चरण में सिर्फ 30 सेकंड की वृद्धि (इंक्रीमेंट) के साथ खेलना पड़ा। उन्होंने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया, जो उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ, जबकि दिव्या के लिए यह एक चूका हुआ मौका रहा। अन्य मुकाबलों की बात करें तो ओपन वर्ग में मैथियास ब्लूबाउम और जावोखिर सिंदारोव के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। वहीं फैबियानो कारुआना और अनिश गिरी का मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ। हिकारू नाकामुरा और आंद्रेई एसिपेंको ने भी अंक बांटे। महिला वर्ग के एक अन्य मुकाबले में झू जिनर लंबे समय तक बढ़त में नजर आईं, लेकिन अंत में बिबिसारा अस्साउबायेवा के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप में 29 टीमें

एजेंसी (हि.स.)
रांची

यहां बुधवार से शुरू हो रही 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में तीन श्रेणियों में 29 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक चलेगा और टीमें ए, बी तथा सी श्रेणियों में भाग लेंगी। ए श्रेणी की टीमें चैम्पियनशिप खिताब के लिये खेलेंगी जबकि बी श्रेणी की शीर्ष दो टीमों और सी श्रेणी की विजेता टीम को प्रमोशन मिलेगा। ए और बी श्रेणी की आखिरी दो टीमें अगले साल क्रमशः बी और सी श्रेणी में खिसक जायेंगी। ए श्रेणी में बारह टीमों को चार पूल में बांटा गया है और नॉकआउट चरण नौ अप्रैल से खेला जायेगा। पूल ए में मेजबान हॉकी झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र हैं जबकि पूल बी में ओडिशा, हॉकी पंजाब और हॉकी आंध्र प्रदेश हैं। पूल सी में हॉकी हरियाणा, हॉकी मध्यप्रदेश और मणिपुर हॉकी हैं। सभी टीमों को जीतने पर तीन अंक और ड्रॉ पर एक अंक मिलेगा।

वैज्ञानिक ट्रेनिंग और रिकवरी से प्रदर्शन में सुधार होगा: सोनाली शिंगाटे

एजेंसी (हि.स.)
बेल्लारी

भारतीय कबड्डी खिलाड़ी सोनाली शिंगाटे ने आगामी एशियन गेम्स 2026 से पहले चल रहे भारतीय महिला कबड्डी टीम के राष्ट्रीय शिविर में वैज्ञानिक ट्रेनिंग और रिकवरी को प्रदर्शन सुधार की कुंजी बताया है। बेल्लारी स्थित इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में आयोजित इस हाई-परफॉर्मेंस कैंप में टीम की संभावित खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं।

सोनाली शिंगाटे, जो 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप (ढाका) में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं और 2018 एशियन गेम्स में रजत पदक विजेता टीम में भी शामिल थीं, ने कहा कि इस बार ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो खिलाड़ियों के लिए नया अनुभव है। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग करने और अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद मिल रही है। करीब एक दशक का अनुभव रखने वाली शिंगाटे ने बताया कि 27 मार्च से शुरू हुए इस कैंप में वैज्ञानिक तरीकों से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें रिकवरी पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग काफी कठिन है, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है, और यहां इसका अच्छा प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे शरीर जल्दी ढल रहा है।

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में इंडियन रेलवे की ओर से उपविजेता रहने के बाद शिंगाटे ने कहा कि उच्च स्तर पर प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग और रिकवरी के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। उन्होंने माना कि पहले रिकवरी और वर्कलोड मैनेजमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे चोट की संभावना बढ़ जाती थी, लेकिन अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन दोनों में सुधार होगा।

यह कैंप 2 अप्रैल तक चलेगा और इसमें अनुभवी व युवा खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। शिंगाटे ने कहा कि साथ में ट्रेनिंग करने से सीनियर और जूनियर खिलाड़ी एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं, जिससे पूरी टीम का स्तर बेहतर होता है।

राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी मुझ पर अच्छी लगती है: रवींद्र जडेजा

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

आईपीएल 2026 में रवींद्र जडेजा की जर्सी का रंग बदल गया है। जडेजा अब जानी-पहचानी सीएसके की पीली जर्सी की जगह राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में दिख रहे हैं। जडेजा ने कहा है कि उन पर गुलाबी जर्सी अच्छी लगती है। सोमवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके के खिलाफ मैच में जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। सीएसके की पारी की समाप्ति के बाद आरआर में लौटने और अपनी गेंदबाजी पर जडेजा ने बातचीत की। आरआर में अपनी वापसी पर इस दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझ पर गुलाबी रंग अच्छा लगता है। जडेजा ने सीएसके को एक ही ओवर में दो झटके दिए। उन्होंने सरफराज खान और शिवम दुबे जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर सीएसके की कमर तोड़ दी। उन्होंने तीन ओवर में 18 रन देकर दो विकेट लिए। अपनी गेंदबाजी पर जडेजा ने कहा, 'मैं शिवम दुबे को काफी समय से जानता हूं। उसके खिलाफ नेट्स में काफी गेंदबाजी की है, इसलिए पता है कि वह स्पिनरों का सामना कैसे करते हैं। मैं इसके लिए तैयार था और मैंने ऑफ-स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की। मुझे पता था कि वह मेरे खिलाफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा कि विकेट थोड़ा चिपचिपा है और गेंद टर्न हो रही है, इसलिए मुझे गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया। मेरा काम बस सही जगहों पर गेंद डालना था और बाकी काम पिच पर छोड़ देना था।'

अप्रैल फूल डे 2026: हंसी-ठिठोली और स्वस्थ मनोरंजन का वैश्विक पर्व

हर साल की तरह इस साल भी 1 अप्रैल के दिन पूरी दुनिया भर में 'अप्रैल फूल डे' मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा दिन है जब दोस्तों और परिवार वालों के साथ लोग मजाक करते हैं। एक-दूसरे को मजाक के अलावा मूर्खतापूर्ण चुटकुले भी सुनाते हैं और साथ में इस दिन को मस्ती भरे अंदाज में मनाते हैं। जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो 'अप्रैल फूल' चिल्लाते हैं। हर कोई इस दिन को अपने लोगों के साथ तरह-तरह से मनाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसकी शुरूआत कैसे हुई होगी या फिर इसे क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं।

'अप्रैल फूल डे' का इतिहास

कई इतिहासकारों का मानना है कि 1582 में इसकी शुरूआत हुई थी, जब फ्रांस ग्रेगोरियन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर में बदल गया था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार, नया साल 1 अप्रैल के आसपास शुरू होता है। इसलिए, कुछ लोग, जिन्हें कैलेंडर में बदलाव की खबर देर से मिली, वे मार्च के अंत में नए साल का जश्न मनाते रहे और इसके लिए उनका मजाक उड़ाया गया। नया साल 1 जनवरी तक चला गया था और जो इसे स्वीकार नहीं करते थे उन्हें 'अप्रैल फूल' कहा जाता था इसी के साथ फ्रांस में, अप्रैल फूल डे को 'प्वाइसन डी एवरिल' के रूप में जाना जाता है, जहां फ्रांसीसी बच्चे अपने दोस्तों की पीठ पर एक कागज की मछली चिपकाते हैं और जब प्रैंक करने वाले व्यक्ति को यह पता चलता है, तो उनका दोस्त 'पोइसन डी'विल' चिल्लाता है। 18वीं सदी के दौरान, अप्रैल फूल डे पूरे ब्रिटेन में फैल गया। स्कॉटलैंड में अप्रैल फूल्स डे दो दिनों तक चलता है, जहां शरारत करने वालों को गौक्स (कोयल पक्षी) कहा जाता है। अप्रैल फूल डे को ऑल फूल्स डे के रूप में भी जाना जाता है।

'अप्रैल फूल डे' का महत्व

यह विशेष दिन मस्ती, आनंद और खुशी से भरा होता है। यह केवल चुटकुले साझा करने और अपने दोस्तों और प्रियजनों को प्रैंक करने के बारे में नहीं है बल्कि खुशियां फैलाना के लिए होता है। चुटकुले और हँसी साझा करने से पूरे वातावरण में खुशी और आनंद फैल जाता है। इस अवसर को दुश्मनों को और दोस्तों को करीब लाने के रूप में भी देखा जाता है।

पुराने कैलेंडर की भूमिका

दरअसल, पहले यूरोप में नया साल मार्च के अंत से अप्रैल की शुरूआत तक मनाया जाता था। जब नया कैलेंडर आया, तो तारीख बदल गई लेकिन जिन लोगों ने पुरानी परंपरा को अज्ञानता वश जारी रखा, उनका और पुरानी परंपरा का मजाक बनने लगा। हालांकि अप्रैल फूल मनाने की कुछ अन्य मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे प्राचीन रोमन त्योहार हिलारिया से जोड़ते हैं। वहीं कुछ इसे मौसम परिवर्तन और वसंत ऋतु की मस्ती से जोड़ते हैं।

अप्रैल फूल डे कैसे मनाया जाता है

प्रैंक और मजाक: इस दिन लोग अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ हल्के-फुल्के मजाक करते हैं। **सोशल मीडिया प्रैंक्स:** आजकल कंपनियां और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी मजेदार फेक अनाउंसमेंट करती हैं। **मीडिया प्रैंक:** कई बार न्यूज चैनल और वेबसाइट्स भी फनी खबरें चलाकर लोगों को चौंकाते हैं।

अप्रैल फूल डे पर रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मजाक ऐसा हो जिससे किसी को चोट या दुख न पहुंचे। ये दिन हंसी मजाक के जरिए खुश रहने का मौका है। ऐसे में संवेदनशील विषयों पर प्रैंक न करें। मजाक करते समय बच्चों और बुजुर्गों के साथ सावधानी रखें।

मजाक और प्रैंक्स के बदलते सामाजिक आयाम

आज के दौर में अप्रैल फूल केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रह गया है। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ और टेक दिग्गज भी इस दिन अपने ग्राहकों के साथ दिलचस्प मजाक करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कंपनियां किसी ऐसे काल्पनिक उत्पाद की घोषणा कर देती हैं जो सुनने में असंभव लगता है, और बाद में उसे एक प्रैंक घोषित कर दिया जाता है। इससे कंपनियों को न केवल पब्लिसिटी मिलती है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ एक हल्का-फुल्का जुड़ाव भी बनता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हंसी और विनोद मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अप्रैल फूल डे जैसा अवसर तनावपूर्ण जीवन में कुछ क्षणों की राहत लेकर आता है। हालांकि, समाजशास्त्रियों ने आगाह किया है कि मजाक की एक गरिमा होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से संकट में डालना इस दिन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है।

वैश्विक स्तर पर विभिन्न नाम

फ्रांस में इस दिन को 'पॉइसन डी'एप्रिल' कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'अप्रैल फिश'। वहाँ बच्चे कागज की मछलियाँ बनाकर दूसरों की पीठ पर चिपका देते हैं। वहीं स्कॉटलैंड में इसे 'हंटिगॉवे डे' के नाम से जाना जाता है, जहाँ यह पर्व दो दिनों तक मनाया जाता है। भारत में भी इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

हंसी के साथ जिम्मेदारी भी

अप्रैल फूल डे हमें सिखाता है कि जीवन को हमेशा गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। हंसी-मजाक रिश्तों में ताजगी लाता है और कड़वाहट कम करता है। लेकिन, 31 मार्च की रात से शुरू होने वाले इस सिलसिले में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी हंसी किसी दूसरे की परेशानी का सबब न बने। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, मजाक और अफवाह के बीच के अंतर को समझना ही इस दिन की असली सार्थकता है। कल जब आप किसी को 'मूर्ख' बनाएं, तो सुनिश्चित करें कि उसके बाद होने वाली हंसी दोनों तरफ से साझा हो।

चंडीगढ़ पीड़ित सहायता योजना, 2018: अपराध पीड़ितों के लिए एक जीवनरेखा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की चंडीगढ़ पीड़ित सहायता योजना, 2018 अपराध के पीड़ितों के लिए एक संवेदनशील जीवनरेखा के रूप में कार्य कर रही है, जो न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें गरिमा, सहारा और पुनर्वास का मार्ग भी उपलब्ध कराती है। यह योजना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ए (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप) के तहत अधिसूचित की गई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शों के अनुपालन में लागू की गई है, ताकि गंभीर अपराधों के पीड़ितों को त्वरित और सार्थक सहायता सुनिश्चित की जा सके।

यह पीड़ित-केंद्रित पहल यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अम्ल हमले, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध, भीड़ हिंसा/लिंचिंग, गंभीर चोट, जलने की घटनाएं, मृत्यु तथा अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को व्यापक सहायता प्रदान करती है। योजना की प्रमुख विशेषताओं में एक समर्पित पीड़ित मुआवजा कोष की स्थापना शामिल है, जिसे भारत सरकार के अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान, जन दान तथा न्यायालयों द्वारा लगाए गए जुमार्नों से वित्तपोषित किया जाता है। योजना के अंतर्गत तत्काल चिकित्सा, आपातकालीन और पुनर्वास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतरिम राहत का भी प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि 1 लाख से 10 लाख तक निर्धारित है, जो चोट या हानि की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती है। अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए विशेष त्वरित प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 15 दिनों के भीतर 1 लाख की अंतरिम सहायता तथा 10 लाख तक अतिरिक्त मुआवजा शामिल है।

योजना के तहत मुआवजा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। नाबालिगों, अनाथों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सावधि जमा (एफडी) जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पीड़ित दिए गए मुआवजे से असंतुष्ट हो, तो उसे अपील करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

मुआवजा संरचना (योजना दिशा-निदेर्शों के अनुसार)

मृत्यु, बलात्कार एवं अप्राकृतिक यौन उत्पीड़नः 5 लाख से 10 लाख, चोट के मामले (गंभीर/साधारण): अधिकतम 5 लाख. जलने के मामलेः 2 लाख से 8 लाख, अम्ल हमले के मामलेः 3 लाख से 10 लाख (निरंतर चिकित्सा एवं पुनर्वास सहायता सहित), मानव तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास हेतुः अधिकतम 10 लाख। ये प्रावधान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) की 2018 की मुआवजा योजना के अनुरूप हैं, जो एक प्रगतिशील और पीड़ित-अनुकूल दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 17.02.2026 को जारी अधिसूचना (01.04.2026 से प्रभावी) के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन नियम, 1999 के तहत अम्ल हमले के पीड़ितों के लिए 10,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है। योजना की प्रभावशीलता को दशार्ते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), यू.टी. चंडीगढ़ ने पिछले पांच वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के पीड़ितों को 5.56 करोड़ की मुआवजा राशि वितरित की है। वित्तीय वर्ष 2025झ्र26 के दौरान 16 पीड़ितों को 77.50 लाख की राशि प्रदान की गई है, जो पीड़ित पुनर्वास और न्याय तक पहुंच के प्रति प्राधिकरण की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह पहल माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं संरक्षक-प्रमुख, एसएलएसए, यू.टी. चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। एसएलएसए, यू.टी. चंडीगढ़ के सदस्य सचिव ने नागरिकों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं तथा मीडिया से इस महत्वपूर्ण योजना के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की है। अनेक पात्र पीड़ित एवं उनके परिवार अभी भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। पीड़ित या उनके आश्रित आवेदन करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या एसएलएसए से संपर्क कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप से त्वरित राहत, चिकित्सा सुविधा और गरिमापूर्ण जीवन पुनर्निर्माण का अवसर सुनिश्चित किया जा सकता है।

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है हरियाणा सरकार: नायब सिंह सैनी

भूपेंद्र शर्मा
पंचकूला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय नेचर कैंप थापली में आए पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने संत कबीर कुटीर में आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर पंजाब के छात्र गदगद नजर आए मुख्यमंत्री ने भी पंजाब के सभी विद्यार्थियों से स्नेहल मुलाकात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए युवाओं के सर्वांगीण विकास संबंधी दृष्टि को साझा किया।

युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि दोनों राज्यों का युवा शिक्षित, आत्मनिर्भर और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाला हो। उन्होंने विद्यार्थियों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर देश सेवा के लिए प्रेरित किया तथा विदेश पलायन की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि युवा अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश में करेंगे तो हरियाणा पंजाब और भारत की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन एक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नेचर कैंप थापली का भ्रमण करते हैं। यह आयोजन हरियाणा के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हरियाणा एवं पंजाब के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को नेचर कैंप थापली भ्रमण हेतु आमंत्रित किया जाता है। यहां छात्र-छात्राएं प्रकृति के सान्निध्य में समय व्यतीत कर पर्यावरणीय तंत्र (ईकोसिस्टम) की कार्यप्रणाली को समझते हैं तथा जैव विविधता, जल संरक्षण और वन संरक्षण जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ-साथ छात्र-छात्राएं राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को लेकर अपने विचार भी सांझा करते हैं।

इस अवसर पर कैंप संयोजक नैंसी, रेंज ऑफिसर संजय, डिप्टी रेंज ऑफिसर विजय नेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम की सराहना की तथा युवाओं को पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

एमसी चंडीगढ़ के आयुक्त ने एसपीसीए में सुविधाओं की समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

आज श्री अमित कुमार, आईएएस, आयुक्त, नगर निगम चंडीगढ़, ने श्री प्रदीप कुमार, आईएएस, विशेष आयुक्त, नगर निगम-सह-सचिव, पशुपालन, यूटी चंडीगढ़ के साथ सेक्टर-38 स्थित सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (एसपीसीए) का दौरा किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम तथा एसपीसीए के अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। यह दौरा एसपीसीए में किए गए सुधार कार्यों की समीक्षा करने तथा वहां रखे गए कुत्तों के रखरखाव, उपचार एवं समग्र परिस्थितियों का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पशुओं के लिए उच्चतम स्तर की देखभाल एवं कल्याण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कुत्तों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, पोषण, दवाइयों की उपलब्धता तथा उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भोजन, दवाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का समुचित स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से संधारित एवं अद्यतन किया जाए। आयुक्त ने आगे निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए तथा एसपीसीए में शीघ्र बायोमेट्रिक मशीन स्थापित की जाए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया तथा निर्देश दिए कि सभी अभिलेखों का संधारण व्यवस्थित एवं कम्प्यूटरीकृत तरीके से किया जाए। कार्यों में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल देते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया कि एसपीसीए से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि पशुओं के बेहतर प्रबंधन एवं कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके।

आतंकवाद प्रभावित परिवारों की मांगों पर राज्यपाल कटारिया द्वारा सकारात्मक विचार का आश्वासन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के आतंकवाद प्रभावित परिवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन में भेंट कर अपनी लंबित मांगों और समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए लंबित वित्तीय पैकेज जारी करने, शहीद पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा देने तथा विशेष पारिवारिक पेंशन लाभों के विस्तार की मांग की। उन्होंने नागरिक पीड़ितों के विधवाओं और माता-पिता के लिए पेंशन बढ़ाने की भी मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में लिए गए नीतिगत निर्णयों को लागू करने, प्लॉट आवंटन और नियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों, विशेषकर रेड और व्हाइट कार्ड धारकों को रियायती या निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। रोजगार से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने पात्रता शर्तों में ढील देकर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा आतंकवाद प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की। साथ ही, आतंकवाद के दौरान विस्थापित होकर बाद में पंजाब लौटे परिवारों के बुजुर्ग सदस्यों के लिए पेंशन सहायता की भी मांग की गई। राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों और विभागों के साथ इस विषय को उठाएंगे और सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से समीक्षा की जाए। राज्यपाल ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के कल्याण, पुनर्वास और सहयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल में सतिंदरपाल सिंह सिद्धू; डॉ. बी.आर. हस्सिर; प्रिंस कुमार; रमन कुमार; जसकरण सिंह; मनजीत कौर; शिंदर कौर; चंचल मनहास; दर्शन कौर; जसबीर कौर; बलविंदर कौर; बीरो; बलबीर कौर; कुलविंदर कौर; वर्षा रानी; पवाना देवी; त्रिप्ता शर्मा; चरणजीत कौर; कश्मीर कौर; साविंदर कौर; रीता जुनेजा शामिल थे।

संक्षिप्त-समाचार

पंचकूला में 2026-27 के कलेक्टर रेट फाइनल

पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जिला पंचकूला की सभी तहसीलों एवं सब-तहसीलों के ड्राफ्ट कलेक्टर रेट पर गठित कमेटी की बैठक आज लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद कलेक्टर रेट को अंतिम रूप दे दिया गया है। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने डीआईओ को निर्देश दिए कि नए कलेक्टर रेट्स को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उन्होंने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नए कलेक्टर रेट एक अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू हों और रजिस्ट्रियां इन्हीं रेट्स के अनुसार की जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। बैठक में एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. कुलदीप, तहसीलदार पंचकूला श्री सुरेश कुमार, तहसीलदार कालका श्री विवेक गोयल, नायब तहसीलदार श्री हरदेव सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचकूला में डिजिटल क्रॉप सर्वे तेज, उपायुक्त के नेतृत्व में कार्य को मिली रफ्तार

पंचकूला। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे (उऊर) का कार्य जिला पंचकूला में तीव्र गति से किया जा रहा है। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन व नेतृत्व में जिला पंचकूला वर्तमान में डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में राज्य भर में छठे स्थान पर है। डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उपायुक्त पंचकूला द्वारा एसडीएम पंचकूला, एसडीएम कालका तथा जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से कार्य की निरंतर समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इस संबंध में दोनों एसडीएम द्वारा फील्ड में जाकर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि निर्धारित समयावधि में कार्य को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के सफल क्रियान्वयन से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर एवं पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और जिला पंचकूला को राज्य में शीर्ष स्थानों में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

अशोक नेगी, महानिरीक्षक, बीटीसी के सम्मान में गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन

पंचकूला। प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र भानू, भा0ति0सी0 पुलिस बल में आज श्री अशोक नेगी, पी0एम0जी0, महानिरीक्षक, बी0टी0सी0 के सम्मान में उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बी0टी0सी0 के वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों एवं अन्य स्टाफ ने उपस्थित होकर उनके दीर्घ एवं उत्कृष्ट सेवाकाल को सम्मानपूर्वक याद किया। ब्रिगेडियर जे0एस0 गोराया, उप महानिरीक्षक ने कहा कि श्री अशोक नेगी, महानिरीक्षक ने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान उच्च स्तर की निष्ठा, अनुशासन एवं समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने अपनी 37 वर्षों से अधिक की अद्वितीय सेवा के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए फोर्स की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनें अदम्य साहस, समर्पण एवं कार्यकुशलता से सीमा सुरक्षा के अतिरिक्त आतंकवाद एवं नक्सलवाद विरोधी अभियानों का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया। उनके अदम्य साहस एवं वीरता को भारत सरकार एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा भी प्रमाणित किया गया। अधिकारी को उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च पदक पुलिस मैडल फार गैलेंट्री, पुलिस मैडल फार मैरिटोरियस सर्विस एवं पुलिस मैडल फार डिस्टिंग्विस सर्विस से भी विभूषित किया गया है। इस दौरान श्री अशोक नेगी, महानिरीक्षक के बैचमेट एवं वरिष्ठ अधिकारी, वैटरन, उनके मित्रगण, पारिवारिक सदस्य एवं समस्त बी0टी0सी0 परिवार के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रिवायत 2026 में झलकी युवा प्रतिभा और सेवा भावना का संगम

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

एसडी रोटरैक्ट की ओर से आयोजित रिवायत 2026ह्न केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव ही नहीं, बल्कि प्रतिभा और सामाजिक सरोकारों का जीवंत मंच बनकर उभरा। इसमें ट्राइसिटी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया, जिससे कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे समाजसेवा और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जोड़ा गया था। रिवायत 2026ह्न ने संगीत, कला और प्रतिभा का ऐसा संगम प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

महोत्सव की मुख्य आकर्षण रही शानदार संगीत प्रस्तुतियां, जिनमें गायक माहि ने अपनी ऊर्जा और सुरों के जादू से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने मशहूर गायक शान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन दिया। इसके अलावा अनन्या शर्मा ने भी अपनी दमदार प्रस्तुति से माहौल को और भी जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रगति नागपाल की प्रस्तुति ने चार चांद लगा दिए। उनकी उपस्थिति और प्रदर्शन ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।

महोत्सव के तहत कई आकर्षक और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनमें रंगमंचह्न (डांस प्रतियोगिता), नजाकतह्न (मॉडलिंग प्रतियोगिता), बैटल ऑफ द बैंड्सह्न (संगीत प्रतियोगिता) और ई-गेमिंग प्रतियोगिता प्रमुख रहीं। इन प्रतियोगिताओं में युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा, ऊर्जा व रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। हर प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित किया और प्रतिभागियों के उत्साह ने पूरे माहौल को जीवंत बनाए रखा। मनोरंजन के साथ-साथ यह आयोजन एक सामाजिक संदेश भी लेकर आया। कार्यक्रम के माध्यम से जुटाई गई पूरी राशि सेक्टर-23 स्थित एक्सेस लाइफह्न में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के सहयोग के लिए समर्पित की गई। इस पहल ने रिवायत 2026ह्न को सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सेवा की मिसाल बना दिया।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा के अनुसार, रिवायत 2026ह्न जैसे आयोजनों का उद्देश्य युवाओं को एक मंच प्रदान करना और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित एसडी रोटरैक्ट टीम ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और बड़े स्तर पर आयोजित करने की बात कही। कुल मिलाकर, यह महोत्सव सेवा, सहानुभूति और सामुदायिक उत्थान की भावना को साकार करता नजर आया, जिसने इसे एक सार्थक और प्रेरणादायक पहल बना दिया।

तरुण भंडारी और बंतो कटारिया ने 'साईं की पाठशाला' के बच्चों संग किया डांस

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

समाज के वंचित, स्लम और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने वाली संस्था 'साईं की पाठशाला' में आज एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस पाठशाला के प्रांगण में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया ने भी शिरकत की। अतिथियों का स्वागत पाठशाला के संचालक व समाजसेवी अनिल थापर ने किया।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने शिक्षा और अन्य गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पाठशाला के तकरीबन 200 बच्चों के परीक्षा के परिणाम आने पर बच्चों को प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) देकर सम्मानित किया व बच्चों का मुंह मीठा कराने के लिए सभी को मिठाइयां भी वितरित की गईं, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस पूरे आयोजन का सबसे मुख्य और भावुक आकर्षण तब देखने को मिला जब औपचारिकता और प्रोटोकॉल से परे हटकर मुख्य अतिथि तरुण भंडारी और नेत्री बंतो कटारिया नन्हे-मुन्ने बच्चों के आग्रह पर खुद को रोक नहीं पाए और उनके साथ जमकर डांस किया। बच्चों के साथ कदम थिरकाते अतिथियों को देखकर पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन के साथ नंगल के विकास में तेजी लाई

नंगल झील पर उत्तरी भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा: भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
नंगल

नंगल को आधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 75 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की शुरूआत की। इसमें उत्तरी भारत का पहला ग्लास ब्रिज, कारगिल शहीद कैप्टन अमोल कालिया के नाम पर 23 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और शिक्षा बुनियादी ढांचे में बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन पहलों को विकास में वर्षों से आई खामियों को दूर करने की दिशा में निर्णायक कदम बताते हुए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की रूपरेखा दी, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उद्योग-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा तक पहुंच और पंजाब की खेतीबाड़ी की रीढ़ को मजबूत करने के लिए भाखड़ा नहर के बराबर बड़े स्तर पर पानी प्रदान करना शामिल है।

इस कदम को राजनीतिक विरोध से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के कारोबार की सरपरस्ती और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने वालों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग नौकरियों, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ईमानदार शासन के मॉडल की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को 75 करोड़ रुपए के विकास कार्य समर्पित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, अकालियों पर पीढ़ियों की नरसंहार का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नशे के व्यापार को सरपरस्ती दी थी और उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे का व्यापार फैला था। इन नेताओं के हाथ अपने सरकारी वाहनों में राज्य में सप्लाई किए गए नशे का शिकार हुए लाखों युवाओं के खून से रंगे हुए हैं। यह पाप माफ नहीं किए जा सकते और इन नेताओं को लोगों द्वारा उनके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।

अकाली लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ये मौकापरस्त नेता हैं जो अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार गिरगिट की तरह अपना रंग और पक्ष बदलते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद को किसान बताकर लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन क्या वे बता सकते हैं कि कोई अनाज उत्पादक बसों का बड़ा बेड़ा और गुड़गांव में एक आलीशान होटल कैसे बना सकता है? यह सब अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए राज्य और इसके लोगों के हितों को बेचकर बनाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, सुखबीर सिंह बादल ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है और रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए कार्यकताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अकाली रैली में वही भीड़ दिखाई देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बेमिसाल कामों के कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जिस कारण वे बेबुनियाद और तर्कहीन बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों के आधार पर ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, जो कभी संभव नहीं होगा।

पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पूर्व उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए, लेकिन कोटकपूरा, बहिबल कला और अन्य जगहों पर जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई और बेकसूरों को मारा गया, उनके बारे में चुप क्यों हैं? ये सारी घटनाएं उनके शासन के दौरान हुईं। वे इन बेअदबी की घटनाओं को भूल गए हैं और मानते हैं कि लोग भी इन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका परिवार इसमें शामिल था। उनकी ह्यपंजाब बचाओ यात्राह्न असल में ह्यपरिवार बचाओ यात्राह्न है। 15 साल राज्य को लूटने के बाद उन्हें यह बताना चाहिए कि वे पंजाब को किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकालियों ने सूबे को बुरी तरह लूटा है, पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक रूप से कुचला है और माफिया को सरपरस्ती दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, सीनियर ह्यआपह्न नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।